

तीन सप्ताह की छुट्टी के बाद, राहुल गांधी अपने देश लौटे

भाजपा में काफी जिज्ञासा व उत्कण्ठा है कि राहुल कांग्रेस व देश के सम्मुख प्रस्तुत गहन समस्याओं के बावजूद इतनी बेफ़्रिकी से विदेश कैसे निकल जाते हैं

-रेणु मिश्रल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 13 जुलाई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगभग तीन सप्ताह के राजनीतिक अवकाश के बाद दिल्ली लौट आए हैं। अवकाश के दौरान उन्होंने राजनीति की व्यस्तताओं से दूर रहकर फीफा विश्व कप का एक मैच देखा, स्कैंडिनेवियाई देशों की यात्रा की और कुछ समय विश्राम किया।

लेकिन, भारतीय जनता पार्टी को यह सब पच नहीं रहा है। उसने राहुल गांधी के इस विदेश दौरे को लेकर उन पर निशाना साधा है। भाजपा सवाल उठा रही है कि कांग्रेस और विपक्ष के सामने मौजूद अनेक चुनौतियों के बावजूद, राहुल गांधी इतने लंबे समय तक विदेश में समय कैसे बिता सकते हैं।

कांग्रेसी सूत्रों का कहना है कि क्या भाजपा को इस बात की चिन्ता नहीं होनी चाहिए कि जब देश के भीतर अनेक

■ राहुल गांधी ने हाल ही में इन छुट्टियों में फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल मैच देखे और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में आनंदपूर्वक भ्रमण करके लौटे हैं। भाजपा का कटाक्ष है, क्या उनके आगमन के इंतज़ार में समस्याएं व मुद्दे “कोल्ड स्टोरेज” में शांति से ठंडी हवा खाते रहेंगे?

■ कांग्रेस का खेमा जवाबी ताना मार रहा है, प्र.मंत्री ने देशवासियों को मितव्ययता और विदेश यात्रा पर न जाने की सलाह दी, पर वे स्वयं इस परामर्श का खुला उल्लंघन करते हुए, एक के बाद एक विदेश यात्राओं का सिलसिला जारी रखे हुए हैं।

■ राजनीतिक हलकों की चर्चाओं के अनुसार, राहुल 17 जुलाई को देहरादून जाएंगे तथा उसी के बाद, कांग्रेस पूरी तरह से हरकत में आएगी।

गंभीर समस्याओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है, तब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी लगातार विदेश यात्राओं में इतना समय क्यों व्यतीत करते हैं।

ज्ञातव्य है कि प्रधानमंत्री मोदी ने बड़े जोर-शोर से देशवासियों से अपील की थी कि वे विदेश यात्राओं से बचें, कम से कम खर्च करें और भविष्य के

लिए बचत करें।

राहुल गांधी के सामने इस समय पार्टी के भीतर विभिन्न चुनौतियों के साथ-साथ, विपक्षी गठबंधन को मजबूत करने की जिम्मेदारी भी है। विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में विपक्षी एकजुटता को लेकर महत्वपूर्ण रणनीति तैयार की जानी है।

इसके अलावा, कांग्रेस नेतृत्व को राजधानी दिल्ली सहित, कई राज्यों में उत्पन्न राजनीतिक और संगठनात्मक परिस्थितियों से भी निपटना है।

सूत्रों के अनुसार, राहुल गांधी 17 जुलाई को देहरादून का दौरा करेंगे। इसके बाद उनके अन्य राजनीतिक कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की जाएगी।

सरकार ने नवम्बर तक पंचायत-निकाय चुनाव नहीं करा पाने के कारण बताये

जयपुर, 13 जुलाई। राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव कराने की समय सीमा निर्धारित करने के सम्बंध में राज्य सरकार की ओर से हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थना पत्र में नवंबर

■ हाई कोर्ट में संयम लोढ़ा की अवमानना याचिका पर सुनवाई आज।

तक चुनाव नहीं करा पाने के कारण बताए गए हैं। वहीं दूसरी ओर, मामले में संयम लोढ़ा की ओर से दायर अवमानना याचिका पर मंगलवार को हाईकोर्ट की खंडपीठ सुनवाई करेगी। राज्य सरकार की ओर से समय बढ़ाने के लिए दायर प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि प्रदेश में करीब पचास फीसदी आबादी ओबीसी वर्ग की है। ऐसे में (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सड़क दुर्घटना में कानोड गाँव के 5 युवकों की मौत

बालोतरा, 13 जुलाई (निसं)। जिले के पचपदरा थाना क्षेत्र में देर रात राष्ट्रीय राजमार्ग-125 पर भांडियावास गांव के पास हुए भीषण सड़क हादसे में गिड़ा क्षेत्र के कानोड गांव के पांच युवकों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई।

जानकारी के अनुसार, कानोड़ गांव के आठ दोस्त स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार होकर पडासला स्थित भोमियाजी के दर्शन करने गए थे। दर्शन करने के बाद

■ आठ दोस्त भोमियां जी के दर्शन कर स्कॉर्पियो से वापस लौटते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गए।

सभी देर रात अपने गांव लौट रहे थे। इसी दौरान भांडियावास गांव के पास उनकी स्कॉर्पियो पहले तो एक अज्ञात वाहन से टकराई और फिर अनियंत्रित होकर आगे चल रहे डंपर में जा घुसी। टक्कर इतनी भीषण थी कि स्कॉर्पियो के परखच्चे उड़ गए। हादसे में रेवांतराम (26) पुत्र गेनाराम जाट, स्वरूपाराम (27) पुत्र मेहराराम जाट, भरत (25) पुत्र बन्नाराम जाट, किशन (27) पुत्र शेराराम जाट तथा भावेश पुत्र कलाराम जाट की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अब लड़ाई अमेरिका, ईरान के बीच, इज़रायल तो पिक्चर में भी नहीं

क्योंकि जंग होर्मुज़ स्ट्रेट के मसले पर है, जिसे अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय मार्ग मानता है, पर, ईरान इस पर अपने नियंत्रण का दावा कर रहा है

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 13 जुलाई। संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर खुला युद्ध छिड़ गया है। दोनों पक्ष एक-दूसरे के सैन्य एवं रणनीतिक ठिकानों पर लगातार हमले कर रहे हैं। युद्धरत पक्षों के बीच शांति समझौते और युद्धविराम को लेकर कतर में चल रही वार्ता फिलहाल ठप हो गई है। पिछले चौबीस घंटों में अमेरिका ने ईरान के अरंदरूनी क्षेत्रों में सैन्य हमले किए हैं। वहीं, ईरान का दावा है कि उसने बहरीन, कुवैत और कतर में अमेरिकी सैन्य परिसंपत्तियों को निशाना बनाकर भारी नुकसान पहुंचाया है। ईरान का कहना है कि इन देशों में तैनात कई पैट्रियट वायु रक्षा प्रणालियों को पूरी

■ इसी के चलते, ईरान ने होर्मुज़ स्ट्रेट से गुजर रहे दो जहाजों पर हमला कर दिया। यहीं नहीं अन्य देशों के जहाजों पर ईरान के हमले में कई भारतीय नाविक मारे गए। जिसकी भारतीय विदेश मंत्रालय ने कड़ी आलोचना की थी।

■ अमेरिका ने अब ईरान के सैन्य संस्थापनों के साथ-साथ नागरिक ठिकानों पर भी हमला शुरू कर दिया है। इसके जवाब में ईरान ने कतर, बहरीन आदि देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों व तेल के कुओं को निशाना बनाया है।

तरह नष्ट कर दिया गया है। इसके अलावा, तेल भंडारण केन्द्रों और अन्य बुनियादी ढांचे को भी नुकसान पहुंचाया गया है। पिछले पंद्रह दिनों की घटनाओं पर नजर डालें तो स्पष्ट होता है कि दोनों पक्षों

तेज करता दिखाई दे रहा है। होर्मुज़ स्ट्रेट में अन्य देशों के जहाजों पर ईरान के हालिया हमलों के कारण अंतरराष्ट्रीय शिपिंग कंपनियों में कार्यरत कई भारतीय नाविकों की मौत हो गई है। भारत के विदेश मंत्रालय ने इन हमलों और भारतीय नाविकों की मृत्यु को कड़ी निंदा करते हुए बयान जारी किया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि अब यह संघर्ष मुख्य रूप से अमेरिका और ईरान के बीच सीमित हो गया है, जिसमें इजरायल की प्रत्यक्ष भूमिका दिखाई नहीं दे रही है। टकराव का केन्द्र अब होर्मुज़ स्ट्रेट बन गया है। अमेरिका इसे एक अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्ग मानता है, जबकि ईरान इसे अपने राष्ट्रीय नियंत्रण (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

.....जब शराब के ठेकेदारों का कार्टल टूटा

टूटने पर लगा, ये इतना आसान था तो पहले क्यों नहीं टूटा

-जाल खंभाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 13 जुलाई। उत्तर प्रदेश के रामपुर में रहने वाले किसान रक्षपाल यादव ने दो साल पहले अपनी आय बढ़ाने और कमाई के नए स्रोत खोजने शुरू किए। इसी दौरान उन्हें शराब की दुकान के लाइसेंस के लिए एक ई-लॉटरी एप्लीकेशन के बारे में पता चला। जब उन्होंने इसकी विस्तृत जानकारी देखी, तो उन्हें यह जानकर हैरानी हुई कि वे आवेदन करने के योग्य हैं। उन्होंने आवेदन किया और किस्मत से उन्हें अपनी शराब की दुकान का लाइसेंस मिल गया। एक दशक पहले यह संभव नहीं था।

2009 से 2018 तक उत्तर प्रदेश में ऐसी आबकारी नीति लागू थी, जिसने छोटे कारोबारियों के लिए दरवाजे बंद कर रखे थे। पूरे राज्य में देशी शराब का थोक कारोबार शराब कारोबारी पॉन्डी

■ उत्तर प्रदेश सरकार ने 2018 में शराब का लाइसेंस लेने की प्रक्रिया को डिजिटल कर दिया और छोटे व्यवसायियों के लिए भी लाइसेंस लेने के द्वार खोल दिए।

■ 2018 से पहले तक यूपी में शराब बेचने की सभी दुकानें पॉन्टी चट्टा जैसे बड़े ठेकेदारों की मिल्कियत थीं, पर लाइसेंस प्रक्रिया को डिजिटल बनाने के बाद इस प्रक्रिया में ईसानी दखलदांजी खत्म हो गई और इसमें कम्प्यूटर ही सब तय करता है।

■ इससे ना केवल बड़े ठेकेदारों का कार्टल टूटा, बल्कि उपकारी राजस्व में भी भारी वृद्धि हुई, इससे पहले उपभोक्ता ज्यादा पैसे देता था, पर, सरकार को मामूली राजस्व ही मिलता था।

चट्टा के वेब समूह के हाथों में था। रक्षाल याद करते हुए कहते हैं, “पॉन्टी चट्टा की दुकानें हर जगह थीं और हम जैसे छोटे लोगों को शराब के कारोबार में आने नहीं दिया जाता था।”

नई व्यवस्था के बारे में वे कहते हैं, “अब लाइसेंस लेने के लिए किसी अफसर या नेता के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें किसी व्यक्ति का कोई (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सीमा के समीप बने ढांचों की जाँच होगी

-कार्यालय संवाददाता-
जयपुर, 13 जुलाई। राजस्थान हाईकोर्ट में भारत-पाकिस्तान बॉर्डर से 50 किलोमीटर क्षेत्र के भीतर बनाई गई इमारतों को हटाने से संबंधित राज्य सरकार और केन्द्र सरकार के नोटिस के खिलाफ कई रिट याचिकायें दायर की। इस मामले पर सुनवाई करते हुये न्यायधीश समीर जैन ने आदेश पारित करते हुए कहा कि यह भारत की सीमा और सुरक्षा से संबंधित है और ऐसे

■ हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि भारत-पाक सीमा के करीब बने ढांचों को हटाने से संबंधित जाँच हेतु कमेटी बनाई जाए।

मामलों में न्याय से बढ़कर व्यावहारिक तथा और हालात जांचकर कदम उठाने चाहिये। अदालत ने जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और बॉर्डर सिक््युरिटी फोर्स (बीएसएफ) के प्रतिनिधियों की कमेटियां गठित करने के आदेश दिये हैं। जो सीमावर्ती जिलों में ऐसी संवेदनशील इमारतों को चिन्हित करें हटाने का कार्य कर सकती हैं।

उन्होंने कहा कि इस कमेटी के सदस्य देश की सुरक्षा को देखते हुए, (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

-यादवेन्द्र शर्मा-

जयपुर, 13 जुलाई। जब एक मामले पर फैसला सुनाने में कई वर्ष निकल जाए तो ऐसे विलम्बित आदेश से न्याय होता है या फिर सिर्फ कानूनी पेचीदगियां ही बढ़ती हैं। ऐसा ही एक जनहित से जुड़ा मामला सामने आया, जिसमें अंतिम फैसला सुनाने में अदालत को एक दशक से भी ज्यादा लगा और फिर दिये गये फैसले को कानूनी पेचीदगियों के चलते वापस लेना पड़ा और अंततोगत्वा बिल्कुल ही विपरीत फैसला हुआ।

इससे सवाल उठता है कि अदालत के समक्ष लंबी और गहन सुनवाई के बाद भी न्याय नहीं हो पाता, क्योंकि न्याय करने की प्रक्रिया में ही बहुत देरी होती है और इस देरी से न्याय का कोई अर्थ नहीं रहता।

दरअसल वर्ष 2012 में हाई कोर्ट की एक खंडपीठ के समक्ष एक जनहित याचिका पेश हुई थी। यह जनहित याचिका जयपुर सांगानेर और उदयपुर आसपास की कॉलोनियों के निवासियों

द्वारा दायर की गई थी। जनहित याचिका में बड़े ही सीधे-सादे शब्दों में एक मुद्दा उठाया गया था कि सांगानेर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को हल्दीघाटी रोड से जोड़ने के लिए जयपुर के मास्टर प्लान में सौ फीट चौड़ी रोड दर्शायी गई है परन्तु इस सौ फीट चौड़ी रोड का निर्माण कार्य पूरा नहीं किया गया है, क्योंकि सड़क के किनारे और कई कई जगह पूरी सड़क पर ही अतिक्रमणकारियों ने कब्जा कर रखा है। अतः याचिकाकर्ताओं ने अदालत से गुहार की थी कि वो प्रशासन को अतिक्रमण हटाने और सौ फीट रोड का निर्माण पूरा करने का आदेश दे। याचिकाकर्ताओं की तरफ से कहा गया था कि चूंकि सड़क का निर्माण नहीं हुआ है और उसपर अतिक्रमणकारियों का कब्जा है तो न तो उन्हें सांगानेर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का और न ही हल्दीघाटी रोड के लिए रास्ता मिलता है। उन्हें जयपुर टोंक हाईवे का इस्तेमाल करना पड़ता है।

मामले की अलग-अलग हुई सुनवाई के दौरान यह भी स्पष्ट हुआ कि

■ ऐसा ही एक किस्सा राजस्थान हाई कोर्ट के समक्ष उजागर होता हुआ दिख रहा है। यह मामला सांगानेर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट और हल्दीघाटी रोड को जोड़ रही सौ फीट रोड से संबंधित है।

■ अदालत 2012 के बाद से कई बार आदेश में कह चुकी है कि मूल नक्शे के अनुसार ही सौ फीट रोड बनाई जाए और अतिक्रमणकारियों को हटाया जाए। यही जनहित का कार्य है।

■ इन्हीं आदेशों के चलते अदालत ने जेडीए, हाउसिंग बोर्ड और नगर निगम को 2015 में 15 महीनों की मोहलत दी थी अतिक्रमणकारियों को हटाने और निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए। परन्तु, जेडीए द्वारा अतिक्रमण तो नहीं हटाया गया उल्टे अवैध कॉलोनियों को रेगुलराइज करने की कार्यवाही अवश्य 2017 तक पूरी कर ली गई।

■ हालत यह है कि वर्ष 2025 में भी जेडीए पहले तो निर्माण कार्य पूरा करने के लिए समय मांगता रहा फिर सड़क का अलाइनमेंट बदलने के लिए निर्णय भी ले लिया। अदालत ने इस निर्णय की निंदा की और जेडीए को फटकार लगाई लेकिन फिर तकनीकी कारणों के कारण अदालत को आदेश वापस लेना पड़ा। अब नई अदालत में सुनवाई के बाद जेडीए के सड़क अदालत को रिअलाइनमेंट के फैसले को अनुमति भी दे दी गई।

उक्त सौ फीट रोड का निर्माण मुख्य तौर पर हाउसिंग बोर्ड द्वारा अवाप्त की गई जमीन पर होना था।

30-40 प्रतिशत हिस्सा जे.डी.ए. द्वारा अवाप्त की गई जमीन पर होना था। हैरानी की बात यह है कि वर्ष 2013 में

ही हाउसिंग बोर्ड द्वारा अदालत में माना गया कि सड़क निर्माण के लिए निर्धारित जमीन पर अतिक्रमणकारियों का कब्जा

है और वह पुलिस विभाग को तीन बार पत्र लिख चुका है कि वह अतिक्रमणकारियों को हटाने में बोर्ड की मदद करे। अदालत में इसी समय के आसपास जेडीए कमिश्नर द्वारा भी एक शपथ पत्र पेश किया गया, जिसमें उन्होंने माना कि अजय मार्ग एक्सटेंशन रोड करीबन 1.8 कि.मी. लंबी है और इसके समीप केवल डॉक्टर्स कॉलोनी और शिवपुरी कॉलोनी ही नियमित कॉलोनी हैं, अन्य पांच कॉलोनियां अनियमित और गैरकानूनी हैं। उन्होंने कहा कि नक्शे में उक्त सड़क की चौड़ाई सौ फीट दर्शायी गई है परन्तु वास्तविकता में कुछ जगहों पर यह केवल 3.7 मीटर से लेकर 7.5 मीटर तक ही रह गई है। इन सब तथ्यों को जानने के बाद अदालत ने वर्ष 2015 में ही जेडीए को आदेश दिये थे कि वह अतिक्रमणकारियों द्वारा बनाई गई इमारतों को चिन्हित करे और साथ ही हाउसिंग बोर्ड को भी आदेश दिए गए थे कि वह अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही करे, परन्तु ज़मीनी स्थिति बदलने और

सड़क का अलाइनमेंट बदलने के कारण अदालत में तोड़-फोड़ की कार्यवाही रोकने के लिए कई याचिकाएं दायर की गईं।

मामले की पेचीदगियों को देखते हुए अदालत ने 2015 में महाधिवक्ता से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी थी। अदालत ने यह भी आदेश दिए थे कि जेडीए, हाउसिंग बोर्ड, नगर निगम और शहरी विकास विभाग मीटिंग कर इस समस्या को सुलझाएं और एक एक्शन प्लान तैयार करें। अदालत ने जेडीए को अलग से यह आदेश भी दिए थे कि वह सड़क के अलाइनमेंट बदलने के मुद्दे पर कार्य करे और 15 महीने में सड़क निर्माण का कार्य पूरा करे। दूसरी ओर उन कॉलोनियों के निवासियों द्वारा अदालत में याचिका पेश कर सड़क के अलाइनमेंट को बदलने की गुहार की गई थी, क्योंकि घरों व दुकानों के निर्माण कर लिये गये थे और उनमें से कइयों के पास पंचायत के पट्टे थे।

हैरानी की बात है कि वर्ष 2017 (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

विचार बिन्दु

दुरात्मा के लिए देश भक्ति अंतिम शरण है। - जॉन्सन

आंकड़ों की सच्चाई से सरकार क्यों घबराई?

आज हम सरकार का मूल्यांकन केवल आरोपों–प्रत्यारोपों के आधार पर करने के बजाय, ठोस आंकड़ों के आधार पर करने का प्रयास करेंगे, जिनमें से कई स्वयं सरकार के अपने ही आंकड़े हैं। हमें यह समझना होगा कि हम कितना ही स्वयं का गुणगान कर लें, आत्म मुग्ध हो जाएं, बड़े-बड़े विज्ञापन छपवा लें, हेडिंग लगावा लें, किंतु सच्चाई तो उन आंकड़ों से ही प्रकट होती है जो धरातल से एकत्रित किए जाते हैं। इस लेख में हम ऐसे ही कुछ आंकड़ों की बात करेंगे जो हमें सच्चाई से रूबरू करते हैं।

गत कई वर्षों से प्रधानमंत्री मोदी एवं सत्ताधारी दल के नेता लगातार यह दावा करते रहे हैं कि भारत की अंतरराष्ट्रीय छवि में बहुत सुधार हुआ है और भारत बहुत तेजी से प्रगति कर रहा है। अन्य देश भारत को बहुत आदर के साथ देखने लगे हैं।

किसी भी देश की अंतरराष्ट्रीय ताकत कितनी है या उसके बारे में अंतरराष्ट्रीय जगत का क्या दृष्टिकोण है, यह परिलक्षित होता है उस देश के पासपोर्ट की ताकत से। इस ताकत को नापा जाता है “ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स” से। इस सूचकांक में भारतीय पासपोर्ट की वर्तमान रैंकिंग विश्व में 125वें स्थान पर है जबकि यह 2014 में 76वें तथा 2021 में 90वें स्थान पर थी। स्पष्ट है, भारतीय पासपोर्ट 2014 से लगातार कमजोर होता जा रहा है। इसका अर्थ यह हुआ कि भारतीयों को लगभग सभी देशों में जाने के लिए वीजा की आवश्यकता होती है। उल्लेखनीय है कि घाना, नामीबिया और ट्यंज्यूनीशिया जैसे देशों को पासपोर्ट रैंकिंग भी भारत से बेहतर है। सरकार को इस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए कि भारत की रैंकिंग खराब हो रही है और यहां के नागरिकों के लिए बाहर जाना अधिक कठिन हो रहा है। इससे यहां के लोगों के अवसर भी कम हुए हैं।

भारतीयों के न्यूजीलैंड जाने के वीजा प्रार्थना पत्रों में से लगभग 25 प्रतिशत अस्वीकार कर दिए जाते हैं। इसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया के वीजा प्रार्थना पत्र में से 15 प्रतिशत खारिज हो जाते हैं। शायद यही कारण है कि कई भारतीय दंपति अमेरिका में जाकर बच्चों को जन्म देते हैं ताकि वे अमरीकी पासपोर्ट के साथ बड़े हों और उनके लिए भविष्य में विभिन्न देशों की यात्रा करना अधिक सुलभ और सुगम हो सके। पासपोर्ट रैंकिंग में विश्व में 125 नंबर पर गिरकर,भारत विश्व गुरु बनने के रास्ते पर अग्रसर है, इस पर विश्वास करना थोड़ा कठिन है। सरकार को इस सच्चाई को स्वीकार करते हुए इस दिशा में उपयुक्त कदम उठाने की आवश्यकता है। किसी भी देश की समृद्धि का पैमाना केवल उसकी जीडीपी नहीं होता है क्योंकि जीडीपी तो जनसंख्या पर निर्भर करती है। भारत के लोगों की प्रति व्यक्ति आय लगभग 22000 रुपए प्रति माह है। यह भारत के सभी राज्यों में बहुत असमान है। जहां दिल्ली में प्रति व्यक्ति आय 50000 महीने है, वहीं बिहार में यह 7700 प्रतिमाह है। “अपर मिडल इनकम ग्रुप” में भारत के केवल पांच राज्य आते हैं जिनकी वार्षिक प्रति व्यक्ति आय 450000 रुपए से अधिक है। ये राज्य हैं– दिल्ली, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक और गुजरात। यदि सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाले राज्यों जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड आदि से तुलना करें तो स्पष्ट होता है कि भारत के राज्यों में ही कितनी असमानता है? जिन राज्यों में शिक्षा और स्वास्थ्य पर अधिक व्यय किया गया और जहां पर आधारभूत संरचनाओं को सुदृढ़ किया गया, वहां पर निवेश भी हुआ और रोजगार के अवसर भी बढ़े। कुछ राज्यों की प्रति व्यक्ति आय इतनी कम है कि इन प्रदेशों के लिए देश की प्रगति का कोई अर्थ नहीं है।

जिन राज्यों ने अपनी जनसंख्या पर प्रभावी नियंत्रण किया, उनकी समृद्धि भी बढ़ी। दिल्ली में “टोटल फर्टिलिटी रेट” केवल 1.9 है जबकि यही बिहार में 2.9 और उत्तर प्रदेश में 2.6 है। उल्लेखनीय है कि टी एफ आर 2.1 होने पर जनसंख्या स्थिर हो जाती है। जनसंख्या तेजी से बढ़ाने वाले राज्यों का प्रतिनिधित्व संसद में परिसीमन के पश्चात अधिक हो सकता है, क्योंकि यह संख्या जनसंख्या पर आधारित होती है। यदि यही क्रम चलता रहा, तो शीघ्र ही किसी भी राजनीतिक दल के लिए केवल उत्तर भारत के राज्यों के समर्थन के आधार पर ही बहुमत प्राप्त करके देश की सरकार बनाना संभव हो जाएगा। यह एक प्रक्रासे से उन राज्यों को सजा देने जैसा होगा जिन्होंने तेजी से प्रगति की तथा शिक्षा और स्वास्थ्य पर अच्छा काम किया। क्या सरकार इस सच्चाई को स्वीकार कर सकती है कि देश में असमानता पहले से कहीं अधिक बढ़ी है? न केवल यह, देश की संपत्ति का केंद्रीकरण कुछ ही में परिवारों में सीमित होकर रह गया है। देश के 1 प्रतिशत लोगों के पास कुल राष्ट्रीय संपत्ति का 40 प्रतिशत है जबकि निचले 50 प्रतिशत के पास कुल 3 प्रतिशत है। यह प्रतिशत पहले से और घटता जा रहा है। अमीर और अधिक अमीर होते जा रहे हैं तथा गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। यह बात कभी भी सरकार के द्वारा स्वीकार नहीं की जाती। केवल यह बताया जाता है कि कितनी जगह मेट्रो बन गईं, चमकमाते स्टेडियम औय वुलेट ट्रेन बना दी गईं।

यदि हम 2047 तक विकसित देशों की श्रेणी में शामिल होना चाहते हैं और वास्तव में विश्व गुरु कहलाने के अधिकारी बनना चाहते हैं तो वर्तमान सच्चाई को स्वीकार करना बहुत आवश्यक है।

वर्ल्ड हैपीनेस इंडेक्स में भारत की स्थिति 116 नंबर पर है। प्रेस की स्वतंत्रता के सूचकांक पर 151 नंबर पर है तथा “करप्शन परसेप्शन इंडेक्स” में भारत की स्थिति 96 नंबर पर है। इन स्थितियों के रहते

यदि हम 2047 तक विकसित देशों की श्रेणी में शामिल होना चाहते हैं और वास्तव में विश्व गुरु कहलाने के अधिकारी बनना चाहते हैं तो वर्तमान सच्चाई को स्वीकार करना बहुत आवश्यक है।
वर्ल्ड हैपीनेस इंडेक्स में भारत की स्थिति 116 नंबर पर है। प्रेस की स्वतंत्रता के सूचकांक पर 151 नंबर पर है तथा “करप्शन परसेप्शन इंडेक्स” में भारत की स्थिति 96 नंबर पर है। इन स्थितियों के रहते हुए यह संभव नहीं है कि हम विकसित भारत या विश्व गुरु का तमगा लेकर घूमते रहें।

या 150 करोड़? सब कुछ केवल अनुमान पर आधारित है। किसी प्रकार की आधिकारिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। किसी भी देश के लिए जगणपना ही योजनाएं बनाने का आधार होती है। यह देश के लोगों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति का विवरण स्पष्ट करती है। सरकार क्यों लगातार जगणपना करने से अब तक बचती रही है? यह सरकार आंकड़ों की सच्चाई का सामना नहीं करना चाहती करना जब कोविड में चुनाव कराए जा सकते हैं तो जगणपना क्यों नहीं?

आंकड़ों के पीछे के सच को स्वीकार करना ही सुधार का रास्ता हो सकता है। यह वैसा ही है जैसे दरी के नीचे की गंदगी को नहीं देखने से सफाई नहीं हो जाती। सरकार को स्वीकार करना उसके बचने की प्रवृत्ति देश के हित में नहीं है, न यह देश की योजना बनाने के लिए सही है। सरकार के पास जब तक वास्तविक आंकड़े ही नहीं होंगे तब तक यह कैसे तय होगा कि कहां कितने विद्यालय, अस्पताल या परिवहन के साधन चाहियें और कितने लोगों को नौकरी चाहिए? बेरोजगारी बहुत तेजी से बढ रही है और वर्तमान शिक्षा व्यवस्था लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने में सफल नहीं हो पा रही है।

यह भी कहा जा रहा है कि सरकार जगणपना के आंकड़ों को भी तोडमरोड कर इबुट्टा करना चाह रही है। प्रणकों को यह कहा जा रहा है कि वे परिवार के पास शौचालय होना मान लें, यदि शौचालय बना हुआ है, चाहे वह काम में नहीं आ रहा हो। इसी प्रकार कोई परिवार यदि पडोस के किसी शौचालय अथवा किसी सार्वजनिक शौचालय का उपयोग कर रहा है, तब भी यह माना जाएगा कि परिवार के पास शौचालय है। इस प्रकार से गलत आंकड़े इकट्ठे करके जो योजना बनेंगी, उस पर हमेशा प्रश्न चिन्ह ही लगा रहेगा।

आंकड़ों को बारीकी से जब तक नहीं देखा जाएगा, तब तक असली स्थिति सामने नहीं आएगी। सरकार ने पहले यह कहा था कि 100 प्रतिशत गांव विद्युतीकृत हो चुके हैं, तो वास्तविकता यह थी कि उस समय भी देश में 3.30 करोड़ परिवार ऐसे थे जिनके पास विद्युत कनेक्शन नहीं था। जब तक घर के अंदर बिजली का कनेक्शन नहीं हो तब तक गांव के विद्युतीकृत होने का कोई अर्थ नहीं है। इसी प्रकार जब तक स्वयं के परिवार में उपयोग में आने योग्य शौचालय नहीं हो तब तक परिवार को शौचालय वाले परिवार की श्रेणी में रखना सही नहीं होगा।

शिक्षा और स्वास्थ्य के आंकड़ों की भी लगभग यही स्थिति है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार लगभग सभी बालक–बालिकाएं विद्यालय में नामांकित हैं। नामांकित होने से कोई बच्चा शिक्षित नहीं हो जाता, यह बात सरकार के अधिकारियों को पता है लेकिन आंकड़ों के पीछे की सच्चाई को मानना नहीं चाहते। आज भी 4.74 करोड़ बच्चे शिक्षा के आलोक से वंचित हो रहे हैं। इसी प्रकार लाखों व्यक्ति स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित होने के कारण कुपोषित भी हो रहे हैं तथा मौत का शिकार भी हो रहे हैं।

कुछ वर्षों पहले नेशनल सैपल सर्वे ऑर्गनाइजेशन के मुखिया को केवल इसलिए हटा दिया गया था कि उन्होंने सरकार के लिए असुविधाजनक आंकड़े सार्वजनिक कर दिए थे। क्या आंकड़ों को रोकने से या उसके पीछे की सच्चाई को स्वीकार नहीं करने से वास्तविकता बदल जाएगी? आवश्यकता इस बात की है कि सच्चाई से घबराने और उससे दूर भागने के बजाय उनका सामना किया जाए और तत्तुसार योजना बनाई जाए ताकि जो कमी है, उसको पूर करने के लिए ठोस प्रयास किए जा सकें। जब उन कमियों को स्वीकार ही नहीं किया जाएगा तो फिर उनको दूर करने के लिए प्रयास करने की बात तो दूर की है।यदि इसी प्रकार से सरकार सच को स्वीकार करने से बचती रही और आंकड़े सार्वजनिक करने से भी बचती रही तो वह सही दिशा में योजनाएं बनाने का काम नहीं कर सकती।

बहुत सारे अंतरराष्ट्रीय संवैधानों को सरकार, भारत के विरुद्ध साजिश बता कर उन आंकड़ों को नकारने का प्रयास करती है। होना तो यह चाहिए कि यदि सरकार को ये आंकड़े अच्छे नहीं लग रहे हैं तो अपने आंकड़े एकत्र करें और उन्हें सार्वजनिक करें ताकि लोग पता कर सकें कि सरकार के आंकड़े कितने सही हैं? सरकार ऐसा करना नहीं चाहती, यही तो समस्या है।

आशा की जानी चाहिए कि जगणपना में लगे प्रणकों को ईमानदारी से वास्तविक स्थिति पता करने के लिए कहा जाएगा न कि बनावटी आंकड़े एकत्र करने के लिए।

ऐसा होने के बाद ही सरकार देशवासियों के लिए सही प्रकार की योजनाएं बनाने में सक्षम हो पाएगी। तब, शायद असमानता को कुछ हद तक कम किया जा सकेगा और भारत की प्रतिष्ठा अंतरराष्ट्रीय जगत में बढ़ाने की दिशा में सही कदम उठाए जा सकेंगे। कुल मिलाकर, आवश्यकता इसी बात की है कि सरकार सच्चाई का सामना करने का साहस करे। यही उसके और देशवासियों के हित में है।

—अतिथि सम्पादक, राजेन्द्र भागवत (पूर्व आई.ए.एस. अधिकारी)



अनुराग शुक्ला

बंगाल में टीएमसी की हार ने कांग्रेस का हौसला बढ़ा दिया है। कांग्रेस इंडिया ब्लॉक के भीतर अपनी स्थिति को फिर से परिभाषित करने का प्रयास कर रही है।

“**कह कबीर कैसे निभे बेर-केर के संग**

वे डोलत मन आपने, उनके फाटत अंग”।

वैसे तो कबीरदास जी ने कई सौ साल पहले एक ऐसी बात लिखी थी जो शत प्रतिशत सही है पर राजनीति में सोलह आने सच्ची बात भी हमेशा पूरी तरह सच नहीं हो सकती है। उत्तर प्रदेश की सियासत में कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के साथ भी आने को तैयार है पर सियासी तौर पर एक–दूसरे

को तौल भी रहे है। गठबंधन की तरफ जाते भी दिख रहे हैं और रास्ते में दोनों पाटियों के बयानों के स्पीड ब्रेकर भी कई सारे हैं।

हाल में ये ही बात तब और बढ़ी जब उत्तर प्रदेश के नए नए प्रभारी बने राजेंद्र पाल गौतम ने लखनऊ आते ही सियासी बयान का गोला दाग दिया। उन्होंने हिस्सेदारी बराबरी की होने की बात की। इसके जवाब में समाजवादी पार्टी ने उनके बयान को राजनीतिक पहचान बनाने कोशिश कहकर अनसुना कर दिया। वैसे राजेंद्र पाल गौतम सिर्फ बातें नहीं कर रहे हैं, उनकी सियासत के कई पहलू हैं। राजेंद्र गौतम वो नेता हैं जो बिना किसी पूर्व सूचना के सांसद तनुज पुनिया के साथ मायावती के घर उनसे मिलने पहुंचे थे। हालांकि मायावती ने उन्हें मिलने नहीं दिया था, जिसके बाद कांग्रेस ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया था। उस दौरान भी चर्चा उड़ी थी कि राजेंद्र और तनुज गठबंधन का प्रस्ताव लेकर मायावती के पास पहुंचे थे। अब राजेंद्र गौतम को ही यूपी का प्रभारी नियुक्त कर दिया गया है।

पहले कारण बताओ नोटिस और कुछ ही दिन में यूपी जैसे सबसे महत्वपूर्ण राज्य का प्रभारी बनना संकेत दे रहा है कि गौतम का ये बयान सिर्फ सुर्खियों में रहने की कवायद भर नहीं है। वैसे ये पहली बार नहीं है कि कांग्रेस ने बराबरी का हक मांगा है। इससे पहले कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद सभी सीटों पर तैयारी और बराबरी की बात कर चुके हैं। उन्होंने तल्लू अंदाज में कहा था हम समाजवादी पार्टी से भीख नहीं मांगते हैं कि वे हमें कितनी सीट देंगे, बराबरी पर बात होगी। समाजवादी पार्टी कौन है हमें सीट देने वाली, हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। विधानसभा चुनाव के लिए कांठोस की तैयारी पूरी है। पश्चिम बंगाल में ममता के साथ जो हुआ उसकी सीख सबको लेनी चाहिए। दअसल बंगाल में टीएमसी की हार ने कांग्रेस का हौसला बढ़ा दिया है। कांग्रेस इंडिया ब्लॉक के भीतर अपनी स्थिति को फिर से परिभाषित करने का प्रयास कर रही है। सीटों के समान बंटवारे की सार्वजनिक घोषणा करके वह संकेत दे रही है कि वह अब उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक जूनियर पार्टनर के तौर पर अपनी पहचान बदलना चाहती है। पार्टी लोकसभा चुनावों के बाद संगठन को मजबूत बना रही है और बराबरी का दर्जा मांग रही है वैसे भी यूपी कांग्रेस का गढ़ रहा है।

ये बात और है कि आज उसके पास सियासी जमीन नहीं है। ऐसे में माना जा रहा है कि वो 170 सीटों तक की मांग कर सकती है जबकि सपा 60–80 सीटें देने का मन बना रही है। सपा के पास पीडीए का समीकरण और संगठन की ताकत है तो कांग्रेस ग्रांड ओल्ड पार्ट का

लेबल लेकर चल रही है। मायावती के घर जाने की कोशिश कर कांग्रेस ने संदेश दे दिया है कि यूपी में सिर्फ सपा के भरोसे नहीं है।

सपा को पता है कि कांग्रेस के नेता चाहे जो बोल लें आखिरी फैसला हाईकमान लेगा। इसलिए अखिलेश ने चुपी साध ली है। उन्हें पता है कि बातचीत की टेबल पर आंकड़े उनके पक्ष में हैं। कांग्रेस यूपी में 37 साल से सत्ता में नहीं है। हर चुनाव में उसकी हालत पतली ही होती गयी है। यूपी में 1989 में कांग्रेस जब सत्ता से बाहर हुई तो 425 सीटों में से सिर्फ 94 सीटें ही जीत पाई। फिर 1991 में 419 में से सिर्फ 46, 1993 में 422 में से सिर्फ 28, 1996 में 424 में से सिर्फ 33, 2002 में 403 में से सिर्फ 25, 2007 में 403 में से सिर्फ 22, 2012 में 403 में सिर्फ 28, 2017 में 403 में सिर्फ सात और 2022 में 403 में से सिर्फ दो सीटें ही जीत सकी है। वो भी ऐसी जो नेताओं ने व्यक्तिगत तौर पर जीती थीं। ऐसे में अखिलेश चुप है बेवजह है बयान नहीं देना चाहता। सीट की जगह जित्ताऊ प्रत्याशी की बात करते हैं।

यूपी में कांग्रेस के अच्छे दिनों में उसकी दलित, पिछड़ा और ब्राह्मणों का सपोर्ट था पर ये कहानी पुरानी है। नई कहानी है कि पिछड़ा और दलित वोटों में अखिलेश की विस्तार चाहते हैं तभी तो पीडीए की राजनीति कर रहे हैं। वहीं

कांग्रेस को भी अपने परंपरागत दलित वोटर तक पहुंचना है। कांग्रेस का विस्तार सपा के वोटों के मूल्य पर होगा। पर इस समय सपा को चिंता वोट की नहीं 10 साल से सत्ता में बैठी भाजपा की है। इससे भी बढ़कर यूपी में 2024 की सफलता को अगर सपा दोहराती है तो इंडी गठबंधन में अखिलेश का रुतबा बढ़ेगा, कद बढ़ेगा। ये बात कांग्रेस को भी पता है। राहुल गांधी आम तौर पर अपने से बड़ा किसी और का सियासी कद बढ़ाश्त नहीं कर पाते हैं। यही वजह है कि बराबरी के बंटवारे की बात हो रही है।

सपा गठबंधन तोड़ना नहीं चाहती, ऐसे में ये भी हो सकता है कि सपा 80 सीटें कांग्रेस के वोटों के और 20–30 सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी अपने सिंबल पर उतार दे। अखिलेश को ये फार्मूला बहुत भाता है। सपा संयमित है क्योंकि उसकी लड़ाई अभी भाजपा से है, कांग्रेस व्याकुल है क्योंकि उसको यूपी की सियासी जमीन चाहिए। अभी ये तो तय माना जा रहा है कि दोनों पाटियां मिलकर ही चुनाव मे ताल ठोकेंगी पर दोनों को पता है कि–

मिले हैं हाथ तो अब साथ चलना लाज़मी है, मगर यहाँ कोई भी समझौता मुप्त का नहीं होता।

—अनुराग शुक्ला, (लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं)

भक्ति संगीत के शिखर पुरुष भजन गायक “रामचंद्र गोयल”

गूंजती है। आपने आकाशवाणी जयपुर में लगभग 18 वर्ष तथा आकाशवाणी जोधपुर में लगभग 26 वर्षों तक भजनों की प्रस्तुतियाँ दीं। वर्ष 1982 में दूरदर्शन के उपग्रह (सैटेलाइट) प्रसारण में आपकी प्रस्तुति हुई। इसके अतिरिक्त दूरदर्शन जयपुर, सीपीसी नई दिल्ली तथा जैन चैनल पर भी आपके भजनों का प्रसारण हुआ। वर्ष 1997 में सीपीसी नई दिल्ली से भी दो बार आपकी प्रस्तुति प्रसारित हुई। देश की जानी–मानी कैसेट्स कंपनियों ने इनके भजनों के कैसेट्स बनाए।

रामचंद्र गोयल ने देश के सभी महानगरों में अपनी भक्ति संगीत साधना का लोहा मनवाया। मीरा बाई की जन्मस्थली मेड़ता में भाद्रपद पवित्रा एकादशी को हरे वन आराधित होने वाले मीरां महोत्सव में वर्षों से भजनों की प्रस्तुति देते रहे हैं। आप दिल्ली दूरदर्शन पर अपनी गायन प्रतिभा से विशिष्ट स्थान बनाने में कामयाब रहे हैं। इनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर जैन टी.वी. चैनल ने लगातार आपका प्रसारण के माध्यम से ही प्रभाव कार्यक्रम का शुभारम्भ किया। आपने सन् 1965 से लेकर 2009 तक लगातार जयपुर व जोधपुर आकाशवाणी के माध्यम से राजस्थानी, हिन्दी में भक्ति संगीत कार्यक्रमों में अपनी आवाज का जादू बिखेरा। खूब द्वारा गाई ‘हैलीयाँ’ ने इनको खूब प्रसिद्धि दिलाई। लोकदेवता बाबा रामदेव, संत तुलसी दास, सूरदास, मीरा बाई, कबीरदास जी, भक्त रैदास जी, संत पीपा आदि जैसे महान संतों की भक्ति रचनाओं को अपने गायन में शामिल किया।

मेहरानगढ़ ट्रस्ट द्वारा प्रसारित जोधपुर के पूर्व महाराज मानसिंह के भजनों की तीन कैसेटों में भी आपने स्वर दिया। मंदिर, शिवालय, रात्रि

जागरण, आकाशवाणी तथा दूरदर्शन पर वर्षों तक भजनों की प्रस्तुतियाँ दी। पिछले 50 वर्षों से भी व्यादा समय से रामायण पाठ, भजन और विभिन्न पदों के गायन से पूरे राजस्थान में अतिलोकप्रियता हासिल की।

गोयल ने सम्पूर्ण राजस्थान ही नहीं, कलकत्ता, दिल्ली, मुम्बई, इन्दौर, अहमदाबाद आदि बड़े शहरों में भजन गायन की स्वर लहरियाँ बिखेर कर लाखों को मंत्रमुग्ध किया। आपको कई वर्षों तक स्वामी रामसुखदास जी महाराज के सानिध्य में भजन गाने का अवसर मिला। उन्होंने संस्कृत हिन्दी, पंजाबी तथा राजस्थानी में गायकों को एक समान स्थान दिया। वे मीरा के भजन, “साँवरिया अरज मीरा री सुगम रे” तथा “मैं जान्यो नाही, हरि सु मिलण कैसे होय..।” की स्वरलहरियाँ बिखरते तो सुनने वालों की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकलती। परम पुज्य स्वामी रामसुखदास जी महाराज की प्रेरणा एवं कृपा से रामचन्द्र गोयल ने अपने निवास पर ही संपूर्ण “श्रीरामचरितमानस” का संस्वर पाठ रिकार्ड किया। इस महान कार्य को पूर्ण होने में लगभग तीन वर्ष का समय लगा तथा संपूर्ण रिकॉर्डिंग घर पर ही सम्पन्न हुई। वर्ष 1981 में स्वामी रामसुखदास महाराज के सान्निध्य में कोलकाता, बोकानेर एवं मुंबई में संपूर्ण “श्रीरामचरितमानस” के पारायण का वाचन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।

हालाँकि वे गृहस्थ जीवन में रहे,मगर लोग उन्हें एक संत के रूप में ही देखते हैं। आज भी ाणमान्य लोग उनके दर्शन की आभिलाषा से उनके घर जाते हैं तो चरण छूकर आशीर्वाद लेना नहीं भूलते। स्वामी रामसुखदास जी के सान्निध्य में रहकर



रामचंद्र गोयल

अपने भजनों व रामचरित मानस को स्वर दिया। स्वामी जी के अलावा देश के नामी–गिरामी संतों व भजन गायकों से गहरा सम्पर्क रहा जिनमें ईश्वरानंद जी, सत्यमित्रानंद जी, अभयगाम जी महाराज प्रमुख हैं।

राष्ट्रदूत संवाददाता से बातचीत करते रामचन्द्र गोयल कहते हैं उन पर सर्वाधिक प्रभाव संतों के जीवन से पड़ा है। प्रोत्साहन के बारे में पूछने पर कहते हैं कि भगवान का प्रोत्साहन ही मुख्य रूप से रहा। रामचंद्र गोयल अपनी समस्त उपलब्धियों का श्रेय अपने आराध्य भावान श्रौराम, माता सीता, लक्ष्मण जी, हनुमान जी तथा अपनी माँ एवं स्वामी रामसुखदास जी महाराज की असीम कृपा को देते हैं। उनका मानना है कि इन्हीं की कृपा से उनका मानव जीवन सफल हुआ। नब्बे वर्ष की उम्र में भी पढ़ने की आदत नहीं छोड़ी है। आज भी वे स्वाध्याय करते हैं। गोयल खुद भजन लिखते भी हैं। अब तक करीब सौ भजन लिख चुके हैं।

–मिश्रीलाल पंवार, लेखक जोधपुर के वरिष्ठ पत्रकार हैं।

ग्रामीण सेवा शिविर में लोगों की मिल रही राहत

बूंदी, (निर्सं)। आमजन को राहत पहुंचाने की दिशा में शुरू किए गए ग्रामीण सेवा शिविरों से ग्रामीणों की रितैर राहत मिल रही है। ग्राम पंचायत घाट का बनाना में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर में दो किसानों की कृषि भूमि के बंटवारे का वृत्त पुराना मामला मौके पर ही हल कर दिया गया। ग्राम बलदेवपुरा निवासी किसान ओमप्रकाश

और मानसिंह अपनी 1.73 हेक्टेयर कृषि भूमि के खाता विभाजन को लेकर काफी समय से परेशान थे। राजस्व रिकार्ड में नाम दफ्त करवाने और भूमि के स्पष्ट बंटवारे के लिए उन्हें दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ रहे थे। ग्राम पंचायत घाट का बनाना में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर में दोनों किसान अपनी समस्या लेकर पहुंचे। मौके पर मौजूद

तहसीलदार और नायब तहसीलदार ने मामले की गंभीरता को समझा और कार्रवाई करते हुए सभी प्रक्रिया पूरी की और भूमि के खाता विभाजन को स्वीकृत कर दिया। भूमि का बंटवारा होते देख किसान ओमप्रकाश और मानसिंह ने राहत की सांस ली। उन्होंने शिविर में मिले समाधान के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और राज्य

सरकार का आभार व्यक्त किया। वहीं जिले के हिण्डोली उपखंड क्षेत्र की रोशदा पंचायत में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर–2026 सीता देवी के लिए राहत लेकर आया। रोशन्दा निवासी सीता देवी अपनी विधवा पेंशन के लिए परेशान थीं और पेंशन के लिए शिविर में पहुंची। शिविर में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता

विभाग के प्रतिनिधि ने उनकी समस्या सुनी। शिविर में बिना किसी देरी के, रा एएसएसी एफ के का उपयोग कर, मात्र 1 मिन्ट के भीतर सीता देवी की पेंशन को मंजूरी मिल गई। पेंशन की स्वीकृति मिलने पर सीता देवी की आँखों में खुशी के आंसू थे। शिविर में मिली राहत के लिए उन्होंने राज्य सरकार का आभार जताया।

राशिफल मंगलवार 14 जुलाई, 2026

आषाढ़ मास, कृष्ण पक्ष, अमावस्या, मंगलवार, विक्रम संवत २०८३, पुनर्वसु नक्षत्र रात्रि १२:१० तक, व्याघात योग दिन ११:५७ तक, नाग करण दिन ३:१४ तक, चन्द्रमा आज सायं ६:४९ से कर्क राशि में संचार करेगा।
ग्रह स्थिति: सूर्य-मिथुन, चन्द्रमा-मिथुन, मंगल-वृष, बुध-मिथुन, गुरू-कर्क, शुक्र-सिंह, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह
आज कुमार योग दिन ३:१४ से रात्रि १२:१० तक है। आज आषाढ़ी अमावस्या, देवपितृकार्य अमावस्या और सोमवती अमावस्या है।
श्रेष्ठ चौघड़िया: चर ९:०९ से १०:५१ तक, लाभ-अमृत १०:५१ से २:१४ तक, शुभ ३:५६ से ५:३८ तक। राहूकाल: ३:०० से ४:३० तक। सूर्योदय ५:४६, सूर्यास्त ७:१९

मेघ	परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। नये-पुनये मित्रों से मुलाकात हो सकती है। परिवजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है।
वृष	व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से संपन्न हो सकते हैं। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी।
मिथुन	मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। मनोबल-आत्मविश्वास बढ़ेगा। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन हो सकता है। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में उचित सोच-विचार हो सकता है।
कर्क	व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। व्यावसायिक आय में वृद्धि हो सकती है। महत्वपूर्ण कार्यों में सफलता से मनोबल-आत्मविश्वास बढ़ेगा। व्यक्तिगत कारणों से मन में असंतोष कायम रहेगा।

सिंह	आर्थिक/वित्तीय मामलों में संतुलन बना रहेगा। व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी। व्यावसायिक प्रयासों में उचित उचित सफलता मिल सकती है।
कन्या	व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। चलते कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। नौकरिपेशा व्यक्तियों के अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है।
तुला	धार्मिक कार्यों में भाग ले सकते हैं। धार्मिक स्थानों की यात्रा का कार्यक्रम बन सकता है। व्यावसायिक अड़चनें दूर होंगे लगेगी। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होगा।
वृश्चिक	चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है।शुभ कार्यों में व्यवधान हो सकता है। मन में असंतोष बना रहेगा। आज आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। आज आज बनते कार्य बिगड़ सकते हैं।

धनु	परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में आपसी सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक संर्षक बनेंगे। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।
मकर	स्वास्थ्य संबंधित चिन्ता दूर होगी।शुभ कार्यों में प्रगति होगी। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन हो सकता है। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। परिवार में मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।
कुंभ	व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। चलते कार्यों में प्रगति होगी। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन हो सकता है। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। परिवार में मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।
मीन	घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। परिवार में सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी। आज परिवार में महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

अजमेर जेएलएन में किसान की मौत, परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया

परिजनों का आरोप है कि अस्पताल स्टाफ ने उनकी जांच रिपोर्ट किसी अन्य महिला मरीज की रिपोर्ट से बदल दी, जिसके आधार पर कई घंटों तक गलत उपचार किया गया

- वहीं आरोप है कि मरीज की गंभीर स्थिति बनने के बाद समय पर ऑक्सीजन, ट्रॉली और गहन चिकित्सा इकाई की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई, जिससे मरीज की जान चली गई**

- परिजनों ने कोतवाली थाने में शिकायत देकर पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच कराने तथा दोषी चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग की**

अजमेर, (निर्स)। अजमेर संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू (जेएलएन) चिकित्सालय में इलाज के दौरान गंभीर लापरवाही का आरोप सामने आया है। भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा निवासी 66 वर्षीय किसान भंवरलाल की उपचार के दौरान मौत हो गई। मृतक के परिजनों का आरोप है कि अस्पताल स्टाफ ने उनकी जांच रिपोर्ट किसी अन्य महिला मरीज की रिपोर्ट से बदल दी, जिसके आधार पर कई घंटों तक गलत उपचार किया गया। इसके साथ ही मरीज की गंभीर स्थिति बनने के बाद समय पर ऑक्सीजन, ट्रॉली और गहन चिकित्सा इकाई की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई, जिससे मरीज की जान चली गई। मामले को लेकर परिजनों ने कोतवाली थाने में शिकायत देकर पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच कराने तथा दोषी चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग की है।

मृतक के मित्र धनराज ने बताया कि भंवरलाल को पेट संबंधी बीमारी

के चलते 9 जुलाई को महात्मा गांधी चिकित्सालय, भीलवाड़ा से अजमेर के जेएलएन अस्पताल रेफर किया गया था। दोपहर करीब तीन बजे उन्हें आपातकालीन इकाई में भर्ती किया गया। प्रारंभिक जांच के बाद चिकित्सकों ने उन्हें सामान्य वार्ड में भर्ती कर उपचार शुरू कर दिया। परिजनों के अनुसार भर्ती होने के बाद पहली रात मरीज की तबीयत में सुधार दिखाई दिया। वे सामान्य बातचीत कर रहे थे और उन्होंने दलिया तथा नारियल पानी भी लिया था। चिकित्सकों ने भी स्थिति सामान्य

बताते हुए उन्हें सामान्य वार्ड में ही रखा। मृतक के पुत्र पप्पू लाल का आरोप है कि अगले दिन नया उपचार शुरू होने के बाद उनके पिता की हालत अचानक बिगड़ने लगी। शाम तक वे परिजनों को पहचान नहीं पा रहे थे, असामान्य व्यवहार करने लगे और रात में दर्द से परेशान होकर बार-बार उठने तथा भागने का प्रयास कर रहे थे। परिजनों ने कई बार ड्यूटी पर मौजूद स्टाफ को स्थिति से अवगत कराया, लेकिन उनकी शिकायतों पर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया गया।

परिजनों का कहना है कि बाद में

उन्हें जानकारी मिली कि मरीज की जांच रिपोर्ट किसी अन्य महिला मरीज की रिपोर्ट से बदल गई थी और उसी आधार पर उपचार जारी रहा। उनका आरोप है कि इसी वजह से मरीज की हालत लगातार बिगड़ती चली गई।

परिजनों के अनुसार 12 जुलाई की रात मरीज की स्थिति अत्यंत गंभीर हो गई। उन्होंने तत्काल आईसीयू में भर्ती करने और बलगम साफ कराने की मांग की, लेकिन समय पर कोई व्यवस्था नहीं की गई।

मजबूर होकर परिजनों को स्वयं ट्रॉली तलाशनी पड़ी, जिसमें लगभग 20 मिनट का समय लाना पड़ा।

इतना ही नहीं, जब मरीज को ऑक्सीजन देने का प्रयास किया गया तो लाया गया सिलेंडर खाली निकला। दूसरा सिलेंडर मंगाने और मरीज को आपातकालीन वार्ड से आईसीयू तक पहुंचाने में भी काफी देर हो गई। परिजनों का आरोप है कि यदि समय रहते आवश्यक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करा दी जाती तो संभवतः मरीज की जान बचाई जा

सकती थी। परिजनों के मुताबिक उपचार में हुई देरी के कारण मरीज ने आईसीयू पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया। आईसीयू में ईसीजी जांच के बाद चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

मृतक के पुत्र पप्पू लाल ने कोतवाली थाने में शिकायत देकर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। उनका कहना है कि एक सामान्य पेट की बीमारी के इलाज के लिए अस्पताल आए किसान की मौत कथित चिकित्सकीय लापरवाही के कारण हुई है। उन्होंने दोषी चिकित्सकों एवं नर्सिंग स्टाफ के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि यदि जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो भविष्य में अन्य मरीज भी ऐसी घटनाओं का शिकार हो सकते हैं। फिलहाल पुलिस ने शिकायत प्राप्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं अस्पताल प्रशासन की ओर से इस संबंध में विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार है।

जोधपुर में हिस्ट्रीशीटर के साथ मिलकर किसान परिवार पर हमला किया

जोधपुर, (कासं)। शहर के एयरपोर्ट थाना क्षेत्र में बासनी बेदा की ढाणी मानपुरा में एक किसान परिवार पर हिस्ट्रीशीटर सहित कुछ लोगों ने हथियारों से लैसे होकर जानलेवा हमला कर दिया। हस्त में वुद्ध बुरी तरह घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए एमडीएमडी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमलावर भागते से समय अपनी बाइक और हथियार मौके पर ही छोड़कर निकल गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर अब जांच आरंभ की है। आरोपियों ने भागते समय जान की धमकी भी दी।

एयरपोर्ट थाना पुलिस ने बताया

कि बासनी बेदा की ढाणी मानपुरा निवासी गोपाल प्रजापत को तरफ से मामला दर्ज कारया गया है। इसमें बताया कि उसके पिता विरमाराम पुत्र फूसाराम रविवार को शाम को अपने खेत में बाढ़ कर रहे थे। तब करीब शाम 6 बजे वहां पर मानपुरा निवासी खिंवरराज पुत्र किशनाराम, गणपत पुत्र यासीराम, गुलाब पुत्र बालुराम तीनों आए और पिता से गाली-गलौच कर मारपीट करनी शुरू कर दी। आरोप है कि उन लोगों ने धारदार हथियार कुल्हाड़ी, कूट और लाठी से हमला किया, जिससे उसके पिता के हाथ में फ्रैक्चर हो गया। सिर में भी गम्भीर चोट

आयी। परिवार की महिलाओं ने जब बीच-बचाव करना चाहा तो उनसे भी मारपीट की गई। आरोपी हथियार और मोटरसाइकिल वहीं पर छोड़कर भाग गए। मारपीट और हमले में घायल उसके पिता को बाद में एमडीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोपी भागते समय पुलिस कार्रवाई नहीं करने की धमकी देकर गए। रिपोर्ट में बताया कि आरोपियों में गणपत नाम का शख्स हिस्ट्रीशीटर है जिसके खिलाफ पहले से ही कई प्रकरण दर्ज हैं। फिलहाल एयरपोर्ट थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है। घायल का अस्पताल में उपचार जारी है।

हथियार बरामद

झुंझुनूं, (निर्स)। शहर में हाल ही में हुई डकैती की वारदात की जांच के दौरान कोवाली थाना पुलिस ने एक और महत्वपूर्ण सफलता हासिल करते हुए गिरफ्तार आरोपी की निशानदेही पर अवैध देशी कट्टा बरामद किया है। बरामदगी के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत नया मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस के अनुसार शहर में गत दिनों हुई डकैती के मामले में गिरफ्तार आरिफ पुत्र सरताज कुरैशी से पूछताछ के दौरान महत्वपूर्ण जानकारी मिली। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस टीम ने नेशनल हाईवे स्थित सिटी कॉलोनी के पास अंसारी कॉलोनी जाने वाले मार्ग पर एक खाली प्लॉट में छिपाकर रखा गया अवैध देशी कट्टा बरामद कर जब्त कर लिया।

हाईवे पर कार अनियंत्रित होकर पलटी, दो जनों की मौत, दो घायल

- चारों दोस्त खाना खाने के लिये निकले थे और वापस कोटा लौटते समय हादसा हो गया**

कोटा, (निर्स)। नान्ता थाना इलाके में रविवार देर रात्रि को कोटा-उदयपुर नेशनल हाईवे पर एक कार अनियंत्रित होकर पलटी खा गई। हादसे में कार में सवार दो जनों की मौत हो गई एवं दो जने घायल हो गये।

जानकारी के अनुसार चार मित्र कार से कोटा आते समय कोटा-उदयपुर हाईवे हैंगिंग ब्रिज के समीप अचानक से भैसों का झुंड आने से तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलट गई, हादसा इतना भीषण था कि कार ड्रिवाइंडर पर चढ़ गई और काफी दूर तक दौड़ती चली गई। हादसे में चारों मित्र क्षतिग्रस्त कार के

भीतर फंस गये। मामले में सामने आया कि चारों दोस्त खाना खाने के लिये निकले थे और वापस कोटा लौटते समय हादसा हो गया। राहगीरों ने जब कार को क्षतिग्रस्त हालत में और चार जनों को कार में देखा तो इसकी सूचना पुलिस व एम्बुलेंस को दी, सूचना पाकर पुलिस

टीम मौके पर पहुंची। नान्ता थाने के सब इंस्पेक्टर घर्मदो लाल ने बताया कि पुलिस को हादसे की सूचना मिली जिस पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची। सब इंस्पेक्टर ने बताया कि चारों मित्र घर से खाना खाने के लिये कार से कोटा-उदयपुर हाईवे पर निकले थे। रविवार देर रात्रि को वापस कोटा आते समय हैंगिंग ब्रिज से पहले तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर ड्रिवाइंडर पर चढ़ गई और पलटी खा गई। एसआई ने बताया कि हादसे में कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और चारों युवक उसमें फंस गए, चारों को उपचार के लिये एम्बुलेंस के जरिये अस्पताल

पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर ने जांच के बाद दो जनों को मृत घोषित कर दिया।

एसआई ने बताया कि हादसे में विज्ञान नगर निवासी अमन (27), दादाबाड़ी निवासी कुंतेश वर्मा (32) की मौत हो गई एवं कार में सवार बसंत बिहार निवासी जगदीश जुमरानी (36) व बोरखेड़ा निवासी दीपेश (36) घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिये अस्पताल में भर्ती कराया गया। एसआई ने बताया कि दोनों मृतकों के शवों का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है, मामला दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।

श्रीडूंगरगढ़ में बेटे ने बुजुर्ग मां की लाठी से पीटकर हत्या की

बीकानेर, (निर्स)। बेटे ने बुजुर्ग मां की लाठी से पीट-पीटकर हत्या कर दी। रात को अपनी पत्नी को जगाकर कहा कि मां मर चुकी है। पत्नी ने चिल्लाकर अन्य परिजनों को उठाया। सभी लोग घर के बाहर सो रही 70 साल की बुजुर्ग मां के पास वीइकर पहुंचे। भाई को देखते ही आरोपी घर से फरार हो गया।

मामला श्रीडूंगरगढ़ थाना इलाके के बाना गांव का रविवार सुबह 4 बजे का है। पुलिस ने आरोपी बेटे रामनिवास को डिटैन कर लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने मौके पर पहुंच कर घटना की जांचकारी ली और बेटे को डिटैन किया है। पुलिस ने मौके पर पहुंच कर घटना की जानकारी ली और बेटे को

- पत्नी को जगाकर बोला मां मर गई, भाई को देखते ही घर से भागा**

- पुलिस ने मौके पर पहुंच कर घटना की जानकारी ली और बेटे को डिटैन किया**

डिटैन किया है। श्रीडूंगरगढ़ थानाधिकारी कश्यप सिंह राघव ने बताया कि बाना गांव में गीता देवी (70) की हत्या के आरोप में बेटे रामनिवास को हिरासत में लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है। रामनिवास

के भाई ओमप्रकाश ने पुलिस को बताया कि देर रात 2 बजे रामनिवास घर में ही इधर-उधर उहल रहा था। उस समय उसकी पत्नी भी जाग रही थी। इसके बाद 4 बजे उसने अपनी पत्नी को उठाया और उससे कहा कि मां मर चुकी है। ये सुनकर उसकी पत्नी चिल्लाई और परिजन भी उठ गए। ओमप्रकाश ने बताया कि घर के सभी लोग जागे और बाहर सो रही मां की ओर दौड़े। रामनिवास मां के पलंग को सरका रहा था। सामने मुझे देखकर वह भाग गया। उसने नींद से उठाकर मां की हत्या की है। पुलिस ने बताया कि युवक मानसिक रूप से अस्वस्थ है। हालांकि उसे हिरासत में लेकर मामले की पूछताछ की जा रही है।

लापता युवती का शव खेत के कुएं में मिला

रामगंजमंडी, (निर्स)। कोटा जिले के मोड़क थाना क्षेत्र में सोमवार सुबह तेलियाखेड़ी स्थित खेत के एक कुएं में अहीर समाज की लापता युवती आरती (26) पुत्री दुर्गालाल का शव मिला। सूचना मिलते ही पुलिस उपाधीक्षक घनश्याम मीणा सहित मोड़क थाना पुलिस

मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से शव को कुएं से बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए मोड़क अस्पताल पहुंचाया। युवती के परिजनों ने 11 जुलाई को उसके लापता होने पर मोड़क थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। इसके बाद से पुलिस और परिजन उसकी

तलाश में जुटे हुए थे। सोमवार सुबह खेत के कुएं में शव मिलने से क्षेत्र में शोक का माहौल है। पुलिस ने थाना मोड़क में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं एफएसएल टीम को भी बुलाया गया। मौत के कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगा।

विराटनगर के जैन नसिया में छह अष्टधातु की मूर्तियां और चांदी के छत्र चोरी

पावटा, (निर्स)। विराटनगर कस्बे के किला-कोटवाली रोड स्थित श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन नसिया में चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है। अज्ञात चोर मंदिर का ताला तोड़कर 6 अष्टधातु की मूर्तियां, 1० चांदी के छत्र और अन्य

- घटना के बाद जैन समाज में रोष, पुलिस प्रशासन से जल्द खुलासा करने की मांग की**

- सूचना पर विराटनगर पुलिस, एमओबी और एफएसएल टीम मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाए**

धार्मिक सामान चोरी कर फरार हो गए। घटना के बाद जैन समाज में भारी रोष व्याप्त है और समाज ने पुलिस प्रशासन



विराटनगर का पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर, जहां चोरी हुई।

से जल्द खुलासा करने की मांग की है। जैन नसिया समिति के अध्यक्ष संतोष जैन ने बताया कि रविवार, 12

जुलाई की रात करीब 11 बजे मंदिर का मुख्य गेट बंद कर सभी लोग अपने घर चले गए थे। सोमवार सुबह करीब 4

बजे मंदिर खोला गया तो मुख्य गेट का ताला टूटा हुआ मिला। अंदर जाकर देखा तो मंदिर में रखे धार्मिक सामान और दानपात्र के आसपास सामान बिखरा पड़ा था तथा कई कीमती धार्मिक वस्तुएं गायब थीं।

सूचना मिलते ही जैन समाज के लोग बड़ी संख्या में मौके पर पहुंचे और पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। चोरी की सूचना पर विराटनगर पुलिस, एमओबी और एफएसएल टीम भी मौके पर पहुंची और घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने के साथ ही संदिग्धों की तलाश में जुट गई है। जैन समाज ने इस घटना को धार्मिक आस्था पर चोट बताते हुए पुलिस प्रशासन से शीघ्र जांच, आरोपियों की गिरफ्तारी और चोरी हुए धार्मिक सामान की बरामदगी की मांग की है। वहीं विराटनगर थाना प्रभारी बाबूलाल का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और जल्द ही चोरी का खुलासा किया जाएगा।

बूंदी, (निर्स)। ईसान की सबसे बड़ी जरूरत उसका अपना आशियाना होता है, लेकिन जब उस आशियाने का मालिकाना हक (पट्टा) पाने के लिए

- पट्टा न होने की वजह से राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा था**
- लंबे समय तक इंतजार करने के बाद इन परिवार ने पट्टा मिलने की उम्मीद ही छोड़ दी थी**

आधी सदी यानी 50 साल गुजर जाए तो उम्मीदें दम तोड़ने लगती हैं। हिंडोली उपखंड क्षेत्र के ग्रामा गांव के घुमंतु/अर्द्ध घुमंतु परिवार के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। लेकिन, राज्य सरकार द्वारा रौशदा ग्राम पंचायत में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर ने इनकी दशकों पुरानी मुश्कद पूरी कर दी। जब परिवार को उनके पुश्तैनी मकान का पट्टा सौंपा गया, तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा।

हरणा निवासी पप्पू नाथ, सुरेश नाथ, अमरनाथ और दिनेश नाथ ने

बताया कि वे पिछले 50 वर्षों से अपने पुश्तैनी मकान के पट्टे का इंतजार कर रहे थे। पट्टा न होने की वजह से वे सरकारी कारगजों में अपने ही घर के



ग्रामीण सेवा शिविर पट्टा तैयार कर परिवार को वितरित किया।

तुरंत संज्ञान लिया और त्वरित कार्रवाई करते हुए हाथों-हाथ पट्टा तैयार कर इन्हें वितरित कर दिया। दशकों पुराना सपना जब हकीकत बनकर उनके हाथों में आया, तो लाभार्थियों के चेहरे खिल उठे। पट्टा पाकर पप्पूनाथ व अन्य सदस्यों ने खुशी जताते हुए कहा कि

जिस काम के लिए उन्होंने आस छोड़ दी थी, वह शिविर में आसानी से पूरा हो गया। राज्य सरकार के इस शिविर ने उनकी उम्मीदों को फिर से ज्वांदा कर दिया है। इस राहत के लिए सभी लाभार्थियों ने राज्य सरकार का आभार जताया।

जयपुर, जोधपुर, अजमेर, अलवर कोर्ट को फिर बम से उड़ाने की धमकी मिली

धमकी भरे ई-मेल के बाद पुलिस, बम निरोधक दस्ता व सुरक्षा एजेंसियों ने तलाशी अभियान चलाया

जयपुर/जोधपुर/अजमेर/अलवर , (कासं)। राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर और जयपुर पीठ, अजमेर जिला न्यायालय परिसर, अलवर अदालती परिसर को सोमवार सुबह एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद न्यायिक और प्रशासन में हड़कंप मच गया। धमकी भरा ई-मेल मिलते ही पुलिस, सुरक्षा एजेंसियां और बम निरोधक दस्ते को सूचना दी गई। धमकी के बाद जोधपुर हाईकोर्ट परिसर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई तथा पूरे परिसर की गहन तलाशी ली गई। जानकारी के अनुसार धमकी किसी अज्ञात ई-मेल आईडी से भेजी गई है। सुरक्षा एजेंसियां ई-मेल के ख़ौत और भेजने वाले की पहचान करने में जुटी है।

जयपुर में हाईकोर्ट में फिर बम ब्लास्ट की धमकी :- जयपुर मे राजस्थान हाईकोर्ट को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी भरा ई-मेल भेजा गया है। इससे पूर्व अब तक हाईकोर्ट को एक दर्जन बार इस तरह की धमकी भरे ई-मेल मिल चुके हैं। मेल मिलने के बाद हाईकोर्ट प्रशासन की ओर से पुलिस उच्चाधिकारियों को इसकी सूचना दी गई। इस पर दौरान जांच एजेंसियों ने मौके पर पहुंचकर हाईकोर्ट की मुख्य बिल्डिंग की गहनता से जांच की। वहीं बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वांड ने चप्पे-चप्पे की



जयपुर हाई कोर्ट परिसर में पुलिस, सुरक्षा एजेंसियां और बम निरोधक दस्ते ने जांच की।

तलाशी ली। हाईकोर्ट प्रशासन को रात 12 बजकर 19 मिनट पर भेजे इस मेल में कहा गया कि जनमानस को नुकसान पहुंचाना हमारा इरादा नहीं है, लेकिन इमारत को नुकसान होगा। इसलिए 6 जिलेटिन बम प्लांट किए गए हैं। सुबह प्रशासन की ओर से मेल देखने के बाद सुरक्षा एजेंसियों को इसकी सूचना दी गई। कोर्ट समय शुरू होने से पहले सुरक्षा एजेंसियों की ओर से तलाशी पूरी करने से न्यायिक कामकाज बाधित नहीं

हुआ। आएदिन धमकी भरा मेल मिलने के बाद भी अब तक इसे भेजने वालों की जानकारी नहीं मिल पाई है। जिसके चलते वकीलों में खासी नाराजगी है। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष प्रहलाद शर्मा ने बताया कि धमकी भरे ई-मेल की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया और सुबह करीब 7:15 बजे सीओ (उत्तर) शिवम जोशी तथा सिविल लाईंस थाना प्रभारी शंभू सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। इसके

अजमेर कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी :-अजमेर जिला न्यायालय परिसर को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद सोमवार सुबह पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां में हड़कंप मच गया। जिला न्यायाधीश को मिले धमकी भरे ई-मेल की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया और सुबह करीब 7:15 बजे सीओ (उत्तर) शिवम जोशी तथा सिविल लाईंस थाना प्रभारी शंभू सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। इसके

बाद पूरे न्यायालय परिसर की घेराबंदी कर सघन तलाशी अभियान शुरू किया गया। जांच पूरी होने के बाद राहत की बात यह रही कि परिसर पूरी तरह सुरक्षित मिला और किसी प्रकार का विस्फोटक नहीं पाया गया।

अब अलवर डीजे कोर्ट को उड़ाने की मिली धमकी :- अलवर में भी सोमवार सुबह अदालती परिसर में धमकी का ई-मेल मिलने से हड़कंप मच गया। यह धमकी कोर्ट की आधिकारिक ई-मेल आईडी पर तमिल भाषा में भेजे गए एक मेल के जरिए दी गई। मेल में दावा किया गया कि कोर्ट परिसर में 6 जिलेटिन बम लगाए गए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां तुरंत अलर्ट मोड पर आ गईं। सोमवार सुबह करीब 9:30 बजे जब अदालती कामकाज के लिए ऑफिस खुला, तब कर्मचारियों की नजर इस मेल पर पड़ी। मेल की गंभीरता को देखते हुए तुरंत अलवर पुलिस अधीक्षक को मामले की सूचना दी गई। धमकी की सूचना मिलते ही पुलिस, बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वायड की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची। ऐतिहासिक महल परिसर स्थित डीजे कोर्ट सहित पूरे अदालती परिसर को खाली करवाकर तलाशी ली गई। करीब दो घंटे तक चली कड़ी जांच के बाद पुलिस को कोई भी संदिग्ध वस्तु या बम नहीं मिला।

कोटा में 59 हजार के जाली नोट बरामद, आरोपी गिरफ्तार

कोटा, (निसं)। ग्रामीण इलाके के बपावर कलां क्षेत्र के बाजार में 100-200 सौ के नकली नोटों को चलाने के प्रयास के दौरान सूचना पर बपावर कलां पुलिस टीम ने 5९300 रुपये के नकली नोटों सहित आरोपी को गिरफ्तार किया है।

ग्रामीण पुलिस अधीक्षक सुजीत शंकर ने बताया कि बपावर पुलिस को सूचना मिली कि एक एसपी नम्बर की बाइक पर एक बैग सहित युवक संदिग्ध अवस्था में घूम रहा है। ग्रामीण एसपी ने बताया कि उक्त सूचना पर पुलिस

■ नकली नोटों को बाजार में चलाने की योजना थी

उपअधीक्षक नरेन्द्र जैन के सुपरविजन में थाने के सहायक उप निरीक्षक रामप्रकाश के नेतृत्व में टीम गठित की गई। गठित टीम ने विशेष कार्ययोजना बनाकर सूचना के आधार पर मौके पर पहुंचे। ग्रामीण एसपी ने बताया कि पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर बपावर कलां के बाजार में नकली नोट खपाने के प्रयास

में संदिग्ध युवक को डिटेन कर उसके बैग की तलाशी ली, तलाशी के दौरान पुलिस टीम ने बैग में से 100 व 200 रुपये के नकली नोट के कुल 59 हजार 300 रुपये बरामद किया। पुलिस टीम ने मौके पर कार्यवाही करते हुए मध्यप्रदेश के थाना गुना पिपरोदा खुर्द निवासी आनंद कुशवाह (38) को गिरफ्तार किया। ग्रामीण एसपी ने बताया कि पृछताछ में सामने आया कि उसने ये नकली नोटा इन्स्टाग्राम मित्र रवि से 2० हजार नकद के बदले में प्राप्त किये थे, पकड़े गये आरोपी से अनुसंधान जारी है,

परिवार पर लाठी-डंडों से हमला, छह घायल

छबड़ा, (निसं)। शहर की मोती कॉलोनी में रविवार को एक परिवार पर कथित रूप से लाठी-डंडों से हमला किए जाने का मामला सामने आया है। पीड़ित ने इस संबंध में पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए कार्रवाई की मांग की है।

पीड़ित सुरेश कुशवाह ने बताया कि रविवार को अचानक 4 से 5 महिला-पुरुष उनके घर पहुंचे और परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट शुरू कर दी। उनके अनुसार हमलावरों ने लाठी-डंडों से हमला किया, जिससे परिवार के कई सदस्य घायल हो गए। कुशवाह के अनुसार, जब परिवार के अन्य सदस्य

बीच-बचाव के लिए आए तो उनके साथ भी मारपीट की गई। घटना में करीब आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। पीड़ित का आरोप है कि हमलावरों ने घर के बाहर खड़ी बैन और बाइक में भी तोड़फोड़ की। घटना के बाद आरोपी मौके से भाग गए। पीड़ित का कहना है कि पूरी घटना आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई है। घटना के बाद पीड़ित परिवार छबड़ा थाने पहुंचा और शिकायत दर्ज करावते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार घायलों का मेडिकल परीक्षण करवाया है।

कॉलेज की छत से गिरा मजदूर

रामगंजमंडी, (निसं)। चेचट कस्बे के नरसिंह जी के बाग में बन रहे निर्माणाधीन सरकारी कॉलेज में सोमवार सुबह एक हादसा हो गया। प्राप्त जानकारी अनुसार कॉलेज निर्माण कार्य में लगे मजदूर कन्हैयालाल पुत्र कालू भील (40) निवासी रावतभाटा रात में निर्माणाधीन भवन की छत पर सो रहे थे। सुबह नौद में अचानक संतुलन बिगड़ने से वह छत से नीचे गिर गया, जिससे उनके सिर और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आईं। हादसे के बाद मौके पर मौजूद अन्य मजदूरों ने तुरंत 108 एंबुलेंस को सूचना दी। एंबुलेंस की सहायता से घायल कन्हैयालाल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चेचट लाया गया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार किया। गंभीर चोट होने के कारण उन्हें तत्काल बेहतर उपचार के लिए झालावाड़ के एसआरजी अस्पताल रेफर कर दिया गया।

बूंदी की सूरज छतरी व मोरडी की छतरी वापस अपने वैभव में लौटेंगी

बूंदी, (निसं)। रानियों के ख्जाब का आईना रही ऐतिहासिक सूरज छतरी व मोरडी की (मयूर) छतरी वापस अपने वैभव में लौटेंगी। वन विभाग ने दोनों छतरियों के लिए 25 लाख की टेंडर प्रक्रिया जारी की है।

सेव अवर हेरिटेज फाउंडेशन के अरिहंत सिंह ने बताया कि सूरज छतरी पर सदस्यों के साथ मिलकर नापकर एस्टीमेट बनाकर वन विभाग को सौंप दिया है, ताकि छतरी में सही तरीके से

■ वन विभाग ने दोनों छतरियों के लिए 25 लाख की टेंडर प्रक्रिया जारी की है

जीर्णोद्धार के कार्य हो सके। वन विभाग ने वेबसाइट पर टेंडर जारी कर दिए हैं। टेंडर प्रक्रिया पूर्ण होते ही सूरज छतरी व मयूर छतरी पर जीर्णोद्धार के कार्य शुरू होंगे। सूरज छतरी में मूर्ति का चबूतरा छतरी का गुम्बद सहित कई कार्य होंगे। मयूर छतरी पर भी पर्यटक आसानी से पहुंचे इसके लिए सुगम मार्ग बनाया जाएगा। कार्य पूर्ण होने के बाद पर्यटकों के लिए सूर्योदय व सूर्यास्त के पॉइंट बनेंगे जो पर्यटन जो नए आयाम देंगे। बालचन्द पाडा पश्चिम

छबड़ा के कड़ैयाबन स्थित विद्यालय में शिक्षकों की कमी

छबड़ा, (निसं)। कड़ैयाबन स्थित उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षकों की कमी को लेकर सोमवार को छात्रों और ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। नाराज विद्यार्थियों ने स्कूल के मुख्य द्वार पर ताला लगाकर प्रदर्शन किया और जल्द से जल्द शिक्षकों की नियुक्ति करने की

■ नाराज विद्यार्थियों ने स्कूल के मुख्य द्वार पर ताला लगाकर प्रदर्शन किया

■ विद्यार्थियों ने जल्द से जल्द शिक्षकों की नियुक्ति करने की मांग उठाई

मांग उठाई। प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों ने बताया कि विद्यालय में लंबे समय से शिक्षकों की कमी बनी हुई है, जिससे उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। उनका कहना था कि इस संबंध में कई बार विभागीय अधिकारियों को अवगत कराया जा चुका है, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं हुआ है इस दौरान छात्रों ने नारेबाजी कर अपनी नाराजगी जताई। विरोध प्रदर्शन में ग्रामीण और



छात्रों और ग्रामीणों ने मांगों को लेकर धरना दिया।

अभिभावक भी शामिल हुए। ग्रामीणों का आरोप था कि सूचना दिए जाने के बावजूद कोई जिम्मेदार अधिकारी करीब एक घंटे तक मौके पर नहीं पहुंचा, जिससे लोगों में नाराजगी और बढ़ गई। प्रदर्शन के दौरान स्कूल गेट पर ताला लगाकर करीब एक घंटे तक धरना दिया गया। कार्यरत कार्यवाहक सीबीईओ चंद्रप्रकाश गुप्ता ने बताया कि विद्यालय में कुल 185 विद्यार्थी नामांकित हैं। स्कूल में शिक्षकों के 17 पद स्वीकृत हैं, लेकिन वर्तमान में केवल 6 शिक्षक ही कार्यरत हैं। उन्होंने बताया कि कई

शिक्षक सेवानिवृत्त हो चुके हैं, जिसके कारण यह स्थिति बनी है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए फिलहाल वैकल्पिक व्यवस्था की गई है तथा रिक्त पदों को भरने के लिए विभागीय स्तर पर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। ग्रामीणों और अभिभावकों ने मांग की है कि विद्यालय में रिक्त पड़े पदों पर शीघ्र शिक्षकों की नियुक्ति की जाए ताकि विद्यार्थियों की पढ़ाई सुचारू रूप से चल सके। और उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके।

जोधपुर में अवैध मॉडिफिकेशन वाली 1० बसें सीज़

नियमों की अवहेलना करने पर जुर्माना लगाया

जोधपुर, (कासं)। जोधपुर में अवैध मॉडिफिकेशन वाली लग्जरी एवं स्लीपर बसों के विरुद्ध सोमवार को कार्रवाई जारी रही। 10 बसों पर कार्रवाई की गई। नियमों के अनुसार संबंधित बसों को सीज़ किया गया तथा उनके चालान बनाए गए।

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के सदस्य सचिव के निदेशानुसार तथा जिला एवं सेशन न्यायाधीश (अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण) जोधपुर महानगर दिनेश त्यागी एवं जिला एवं सेशन न्यायाधीश (अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण) जोधपुर जिला पूर्ण कुमार शर्मा के निर्देशों की पालना में सुरक्षित परिवहन के नागरिकों के अधिकारों की रक्षा तथा वैधानिक प्रावधानों एवं सरकारी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के

उद्देश्य से विशेष अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान बॉम्बे मोटर चौराहा, कल्पतरु बस स्टैंड एवं बारहवीं रोड चौराहा पर जिला विधिक सेवा

प्राधिकरण, जोधपुर महानगर एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा परिवहन एवं पुलिस विभाग की संयुक्त जांच टीम के साथ औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान अवैध रूप से संचालित तथा अनधिकृत संरचनात्मक बदलाव करने वाली स्लीपर एवं लक्जरी बसों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 1० बसों पर नियमानुसार कार्रवाई की गई तथा उन्हें सीज़ कर चालान बनाए गए। विशेष अभियान के दौरान कुल 10 बसों का निरीक्षण किया गया। जांच के दौरान विभिन्न नियमों का उल्लंघन पाए जाने के संबंध में बसों के विरुद्ध नियमानुसार चालान बनाए गए तथा नियमों की अवहेलना करने वाले संचालकों पर

जुर्माना लगाया गया। वहीं जिन बसों में गंभीर अनियमितताएं एवं अनधिकृत संरचनात्मक बदलाव पाए गए, उन्हें मौके पर ही नियमानुसार सीज़ कर दिया गया।

पूरी कार्रवाई को निष्पक्ष एवं प्रभावी ढंग से संपन्न कराने के लिए न्यायपालिका, पुलिस एवं परिवहन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर उपस्थित रहे। आमजन से अपील की गई है कि स्लीपर एवं लग्जरी बसों की जांच यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा जान-माल की हानि रोकने के उद्देश्य से की जा रही है। इसमें सभी नागरिक सहयोग करें। यदि कोई यात्री किसी ट्रेवल्स एजेंसी के विरुद्ध कार्रवाई करवाना चाहता है, तो वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, न्यायालय परिसर, जोधपुर महानगर में संपर्क कर स्थायी लोक अदालत में वाद प्रस्तुत कर सकता है।

नीमकाथाना : कॉजेल में व्याख्याताओं के तबादले से छात्रों में आक्रोश

नीमकाथाना, (निसं)। एसएनकेपी कॉलेज में पांच व्याख्याताओं और एक लैब असिस्टेंट के तबादले के विरोध में सोमवार को छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआई) के आान पर विद्यार्थियों ने कॉलेज का मुख्य द्वार बंद कर राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। छात्रों ने आरोप लगाया कि पहले से ही कॉलेज में शिक्षकों की भारी कमी है, ऐसे में तबादलों से विद्यार्थियों की पढ़ाई पर गंभीर असर पड़ेगा।

प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना था कि कॉलेज में पीटीआई सहित करीब 20 पद पहले से रिक्त हैं। इसके बावजूद दो दिनों पूर्व पांच व्याख्याताओं और एक

■ एसएनकेपी कॉलेज का गेट बंद कर छात्रों ने धरना प्रदर्शन किया

■ कॉलेज में पीटीआई सहित करीब 20 पद पहले से रिक्त हैं

लैब असिस्टेंट का तबादला कर दिया गया, जिससे शैक्षणिक व्यवस्था और अधिक प्रभावित होगी। एसएफआई के जिला सचिव विक्रम यादव ने कहा कि जब कॉलेज पहले से ही स्ट्राफ की कमी से जूझ रहा है तो ऐसे समय में शिक्षकों का तबादला करना विद्यार्थियों के

भविष्य के साथ खिलवाड़ है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या सरकार छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित रखना चाहती है। प्रदर्शन की सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। कॉलेज प्राचार्य संतोष वर्मा ने छात्रों से वार्ता कर उन्हें शांत कराया और उनकी मांगों को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। इसके बाद छात्रों ने प्रदर्शन समाप्त करते हुए प्रशासन को तीन दिन का अल्टीमेटम दिया। छात्रों ने चेतावनी दी कि निर्धारित समय में समाधान नहीं होने पर उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।

पूर्व एसएफआई नेता एवं अधिवक्ता गोपाल सैनी ने कहा कि

कॉलेज में पहले से ही लगभग 20 पद रिक्त हैं। ऐसे में लगातार तबादले शिक्षा व्यवस्था को कमजोर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कॉलेज को धर्मशाला नहीं बनने दिया जाएगा। सरकार छात्रों के हितों की अनदेखी कर रही है। उन्होंने नई शिक्षा नीति पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि वर्तमान व्यवस्था में परीक्षा, प्रवेश और पढ़ाई का पूरा शैक्षणिक कैलेंडर अव्यवस्थित हो गया है, जिसका खामियाजा विद्यार्थियों को भुगतना पड़ रहा है। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने रिक्त पदों को शीघ्र भरने तथा स्थानांतरित किए गए शिक्षकों के तबादले पर पुनर्विचार करने की मांग करते हुए सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की।

बूंदी शहर के ऐतिहासिक दरवाजे अब पर्यटकों को आकर्षित करेंगे

बूंदी, (निसं)। बूंदी शहर के ऐतिहासिक दरवाजे आने वाले दिनों में पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। शहर की प्राचीन धरोहरों को सहेजने और पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इन ऐतिहासिक दरवाजों के संरक्षण व सौंदर्यीकरण का कार्य 14 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। यह पहल भारतीय सांस्कृतिक निधि (इंटेक) चैप्टर द्वारा की गई है।

भारतीय सांस्कृतिक निधि के केंद्रीय कार्यालय के निर्देशन में 14 जुलाई की सुबह इस कार्य का शुभारंभ होगा। कार्यक्रम में जिला कलैक्टर हरफूल

■ ऐतिहासिक दरवाजों के संरक्षण कार्य का शुभारंभ आज होगा

■ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के प्रयासों से स्वीकृति मिली

सिंह यादव सहित अन्य गणमान्य अतिथि मौजूद रहेंगे। यह कार्य लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के बूंदी में पर्यटन और विकास को गति देने के विजन को साकार करने की दिशा में एक अहम कदम साबित होगा।

इंटेक चैप्टर बूंदी के संयोजक राजकुमार दाधीच ने जानकारी देते हुए बताया कि लोकसभा अध्यक्ष के विशेष प्रयासों से ही भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के माध्यम से इस कार्य को स्वीकृति मिली है। उन्होंने कहा कि इन ऐतिहासिक दरवाजों के संरक्षण और सौंदर्यीकरण से न केवल शहर की



बूंदी शहर के ऐतिहासिक दरवाजों के संरक्षण व सौंदर्यीकरण का कार्य होगा।

सुंदरता में चार चांद लगेंगे, बल्कि देशी-विदेशी पर्यटन को भी नए पंख मिलेंगे। शहर की ऐतिहासिक धरोहरों को सहेजने के इस कार्य में आमजन से भी सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की गई है। इंटेक के सह-संयोजक राजेंद्र कुमार भारद्वाज, सदस्य नंद

प्रकाश शर्मा नंजी, अशोक तलवास, जेपी त्रिपाठी, पंकज दादी, मनमोहन अलमेरा, पीयूष पाचक और अनुराग शर्मा आदि ने शहरवासियों से इस संरक्षण कार्य में बढ़-चढ़कर सहयोग करने का आह्वान किया है।

क्षेत्र में अपराध की जिम्मेदारी आईजी व एसपी की होगी- भजनलाल

मुख्यमंत्री ने संगठित अपराध, सायबर क्राइम व नशा तस्करी का पूरा नेटवर्क ध्वस्त करने के निर्देश दिए

जयपुर, 13 जुलाई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को मुख्यमंत्री आवास पर राज्य में कानून-व्यवस्था की समीक्षा करते हुए कहा कि

■ **मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य में कानून व्यवस्था की बैठक में हाल की अपराधिक घटनाओं पर संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा।**

■ **मुख्यमंत्री ने कहा कि डिजिटल अरैस्ट और ऑनलाइन ठगी के मामलों में त्वरित कार्यवाही पर आमजन का विश्वास बहाल करना पुलिस की जिम्मेदारी है।**

अब क्षेत्र में होने वाले अपराधों की जिम्मेदारी सीधे संबंधित आईजी और एसपी की होगी। उन्होंने गृह विभाग एवं पुलिस अधिकारियों को दो टूक कहा कि प्रदेश में अपराध किसी भी सूरत में



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को मुख्यमंत्री आवास पर राज्य में कानून-व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक की।

बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बैठक में कई जिलों के पुलिस अधीक्षकों को फटकार लगाते हुए कहा कि संगठित अपराध, साइबर क्राइम और नशा तस्करी के मामलों में सिर्फ गिरफ्तारी से काम नहीं चलेगा, बल्कि इन अपराधों का पूरा नेटवर्क ध्वस्त होना चाहिए। गोरगुदा में चरागाह भूमि पर अतिक्रमण के मामले में एक वरिष्ठ अधिकारी को उनके निर्देश पर नोटिस भी जारी किया गया। उन्होंने अलवर, श्रीगंगानगर और भरतपुर में हाल में हुई आपराधिक घटनाओं को

लेकर संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध हथियार संगठित अपराध की रीढ़ है और संगठित अपराध को रोकने के लिए इसे तोड़ना बहुत जरूरी है। जिन जिलों में आम्स एन्ट के मामलों में बढ़ोतरी हुई है, वहां अवैध हथियारों की सप्लाई चेन तोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि डिजिटल अरेस्ट और ऑनलाइन ठगी के मामलों में त्वरित कार्रवाई कर आमजन का

विश्वास बहाल करना पुलिस की जिम्मेदारी है।

मुख्यमंत्री ने महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध जघन्य अपराधों को अत्यंत गंभीर बताते हुए ऐसे मामलों में त्वरित, कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए।

बैठक में मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक सहित, मुख्यमंत्री कार्यालय, गृह विभाग एवं पुलिस विभाग के उच्चाधिकारी उपस्थित रहे। वहीं, रैंज महानिरीक्षक एवं समस्त जिलों के पुलिस अधीक्षक वी.सी. के जरिए बैठक से जुड़े।

सरकार ने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
उचित आरक्षण सुनिश्चित करना जरूरी है। ओबीसी आयोग ने 14 अगस्त, 2026 तक राजनीतिक आरक्षण रिपोर्ट पेश करने की सूचना दी है। ऐसे में सरकार विभिन्न श्रेणियों के आरक्षण का विवरण 31 अगस्त तक उपलब्ध करा सकेगी। प्रार्थना पत्र में कहा गया कि राज्य निर्वाचन आयोग ने गत 6 जुलाई को पत्र के जरिए सूचित किया है कि यदि आरक्षण का विवरण 31 अगस्त तक उपलब्ध करा दिया जाएगा तो विभिन्न वैधानिक प्रावधानों और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव चार चरण में और निकाय चुनाव दो चरण में कराने होंगे और इसमें कुल 90 दिन का समय लगेगा। प्रार्थना पत्र में कहा गया कि प्रदेश में करीब 14 हजार ग्राम पंचायतों और तीन सौ से अधिक नगर पालिकाओं के चुनाव होने हैं। ऐसे में संसाधनों को देखते हुए चरणबद्ध चुनाव करना सही रहेगा। ग्राम पंचायत के चुनाव में 50 दिन और शहरी निकायों के लिए 40 दिन लगेगे।

सीमा के ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
जमीनी हकीकत, सुरक्षा सूचनाओं और तथ्यों का आंकलन कर हर मामले पर कार्यवाही करने के लिये उपयुक्त है। इस जानकारी के साथ यह कमेटी किसी भी ईमारत को तोड़ने या किसी भी व्यक्ति को ईमारत खाली करने तथा किसी भी अन्य तरह की कार्यवाही करने के लिये उपयुक्त है। उल्लेखनीय है कि इस मामले में 22 याचिकाकर्ताओं ने याचिका दायर की थी। और जिन्होंने बिना उपयुक्त इजाजत के भारत-पाकिस्तान बॉर्डर के पास दरगाह, मस्जिद, मदरसे आदि का निर्माण किया था, जिसके लिए इन्हें नोटिस दिए गए थे। इस मामले में राज्य सरकार की तरफ से महाविधवा और केन्द्र सरकार की तरफ से एडिशनल सोलोसीजर जनरल पैरवी के लिये पेश हुये थे।

राजस्थान भर के ट्रांसपोर्टर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर

प्रदेश के दस हजार ट्रकों के पहिए थमे, राज्य की सीमाओं पर 30-35 हजार ट्रक अटके

- **ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि सरकार ने नियम तो लागू कर दिए, पर आवश्यक व्यवस्थाएं नहीं कीं।**
- **ट्रांसपोर्ट संगठनों का आरोप है कि राजस्थान में वीएलटीडी लगाने के लिए अधिकृत कंपनियां एक डिवाइस के 25-30 हजार वसूल रही हैं, जबकि अन्य राज्यों में यह डिवाइस 3 से 6 हजार रुपए में उपलब्ध है।**

जयपुर, 13 जुलाई। वीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस (वीएलटीडी), परमिट और ई-डिटेक्शन चालान से जुड़ी समस्याओं को लेकर राजस्थान के ट्रांसपोर्टर सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। राजस्थान ट्रक ट्रांसपोर्ट संघर्ष समिति के आह्वान पर प्रदेशभर में करीब दस हजार ट्रकों ने चक्का जाम कर दिया है। ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि सरकार ने नियम तो लागू कर दिए, लेकिन उन्हें लागू करने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं नहीं कीं, जिसका खामियाजा वाहन मालिकों और ट्रांसपोर्ट कारोबारियों को भुगतना पड़ रहा है। ट्रांसपोर्टरों ने स्पष्ट किया है कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाएंगी, आंदोलन जारी रहेगा।

आंदोलन को लॉजिस्टिक्स एंड ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स एसोसिएशन, जयपुर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स एसोसिएशन, विश्वकर्मा ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, जयपुर परचून ट्रांसपोर्ट यूनियन और ऑल राजस्थान कॉन्ट्रेक्टर कैरिज बस ऑपरेटर एसोसिएशन सहित, प्रदेश के कई प्रमुख ट्रांसपोर्ट संगठनों का समर्थन मिला है। अलवर में ट्रांसपोर्टरों ने रैली निकालकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और बाजार की कुछ दुकानें भी बंद कराईं।

विश्वकर्मा ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष जगदीश चौधरी ने बताया कि प्रदेश में अधिकृत कंपनियों के पास पर्याप्त संख्या में वीएलटीडी डिवाइस उपलब्ध नहीं है। इसके कारण करीब 30

से 35 हजार ट्रक राजस्थान की सीमाओं के बाहर खड़े हैं। यदि ये वाहन आवश्यक प्रक्रिया पूरी किए बिना राज्य में प्रवेश करते हैं तो ई-डिटेक्शन कैमरों के जरिए भारी-भरकम ऑनलाइन चालान होने का खतरा है। वहीं डिवाइस नहीं लगने से नेशनल परमिट और फिटनेस प्रमाण-पत्र का नवीनीकरण भी अटका हुआ है। जयपुर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स एसोसिएशन के संयुक्त सचिव गुलशन नागपाल ने कहा कि ट्रांसपोर्टर वीएलटीडी लगाने का विरोध नहीं कर रहे, बल्कि इसे लागू करने के लिए पर्याप्त समय और व्यवस्था की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि ट्रैकिंग डिवाइस लगने तक अस्थायी परमिट व्यवस्था जारी रखी जाए, ताकि मालवाहक वाहनों का संचालन बाधित न हो।

ट्रांसपोर्ट संगठनों का आरोप है कि राजस्थान में केवल सीमित कंपनियों को वीएलटीडी लगाने के लिए अधिकृत किया गया है। इन कंपनियों द्वारा एक डिवाइस के लिए 25 से 30 हजार रुपए तक वसूले जा रहे हैं, जबकि अन्य राज्यों

में यही डिवाइस करीब 3 से 6 हजार रुपए में उपलब्ध है। एसोसिएशन के प्रवक्ता राजीव त्रेहन ने कहा कि ई-डिटेक्शन प्रणाली के कारण बड़ी संख्या में लाखों रुपए के ऑनलाइन चालान हो रहे हैं। कई बार वाहन मालिकों को इसकी जानकारी तक नहीं होती और बाद में चालानों की लंबी सूची सामने आती है। उन्होंने आरोप लगाया कि आरटीओ और पुलिस की कार्रवाई से ट्रांसपोर्टर लगातार परेशान हैं। केन्द्र सरकार ने एआईएस-140 सुरक्षा मानकों के तहत व्यावसायिक वाहनों में वीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस अनिवार्य किया था। इसके बाद राजस्थान परिवहन विभाग ने वर्ष 2022 से इस व्यवस्था को लागू करना शुरू किया। ट्रांसपोर्ट संघर्ष समिति का कहना है कि यदि सरकार और ट्रांसपोर्ट संगठनों के बीच जल्द सहमति नहीं बनी तो प्रदेश में सीमेंट, स्टील, किराना, कृषि उपज और अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति प्रभावित हो सकती है।

सोशल मीडिया ने नितिन ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
अनिवार्य बनाने की नीति के दौरान “सियान एग्री” की आय में तेज उछाल आया और उसके शेयरों की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हुई। विपक्षी दलों और विश्लेषकों का कहना है कि यह हितों के टकराव का संभावित मामला हो सकता है। उनका सवाल है कि इस नीति को इतनी तेजी से लागू करने के पीछे जनहित है या निजी लाभ। गडकरी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उनके परिवार का चीनी और एथेनॉल से जुड़ा कारोबार पहले से चल रहा है और उन्हें इससे कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं हो रहा है।

गडकरी एथेनॉल को देशहित के लिए बहुत जरूरी मानते हैं। उनका तर्क है कि एथेनॉल के उपयोग से तेल का आयात कम होता है, प्रदूषण घटता है,

गन्ने और अनाज की मांग बढ़ने से किसानों को फायदा होता है और देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होती है। ब्राजील, अमेरिका और थाईलैंड जैसे देशों के सफल कार्यक्रमों का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि ई-20 तकनीकी रूप से सही साबित हो चुका है। उन्होंने यह भी कहा कि इंजनों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचने के दावे “पूरी तरह गलत हैं” और ऐसी आलोचनाओं के पीछे “पेट्रोलियम लॉबी” या उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे राजनीतिक विरोधियों का हाथ है, जो उनकी छवि खराब करना चाहते हैं।

गडकरी ने मीडिया और सोशल मीडिया पर चल रहे दावों को भी गलत जानकारी और एक सोची-समझी मुहिम बताया है, जिसका उद्देश्य इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पहल को कमजोर

करना है। उन्होंने ऐसे संगठनों पर मानहानि का मुकदमा करने की चेतावनी भी दी है।

यह पूरा मामला एक बड़े सवाल को सामने लाता है कि किसानों के हित और तेल आयात में कमी लाने, और दूसरी तरफ बुनियादी ढांचे की तैयारी, ग्राहकों की लागत और शासन की छवि के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। जहां एथेनॉल आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देता है, वहीं गडकरी परिवार के कारोबारी लाभ ने पारदर्शिता को लेकर सवाल भी खड़े किए हैं। जब तक उपभोक्ताओं की शिकायतें जारी हैं और एथेनॉल उत्पादन में पानी की बढ़ती खपत को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं, तब तक सरकार को स्वतंत्र और कड़ी जांच के साथ स्पष्ट जवाबदेही सुनिश्चित करनी होगी, ताकि जनता का भरोसा बना रहे।

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
में लाने का प्रयास कर रहा है। अमेरिका ने ईरान के भीतर स्थित सैन्य प्रतिष्ठानों पर गहरे हमले करते हुए मिसाइल और ड्रोन सुविधाओं को निशाना बनाया है। यह ईरानी ठिकानों पर अमेरिका के नए सैन्य अभियान का दूसरा चरण माना जा रहा है।

इससे पहले, पिछले सप्ताह अमेरिका ने लगभग 140 सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इनमें से अधिकांश ईरान के तटीय क्षेत्र में स्थित थे, जहां से होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर हमले किए जा रहे थे। ओमान के तट के पास से गुजरने वाले जहाज भी ईरानी हमलों से नहीं बच सके।

ईरान ने सबसे पहले अमेरिका द्वारा स्वीकृत समुद्री मार्ग से गुजर रहे दो जहाजों पर हमला किया था। इनमें दो अत्याधुनिक और अत्यंत महंगे विशाल तेल टैंकर भी शामिल थे।

इस घटना के बाद राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने ईरान की कड़ी आलोचना की और उन तटीय सैन्य परिस्परितियों को निष्क्रिय करने का आदेश दिया, जहां से ये हमले किए गए थे। अनेक देशों ने इन हमलों की निंदा की और दोनों देशों के बीच बढ़ते अविश्वास के कारण वार्ता का माहौल भी बिगड़ गया।

बाद में ट्रंप ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए आरोप लगाया कि ईरान अपने वादों से पीछे हट रहा है और उसने अंतरिम

14-सूत्रीय शांति समझौते के तहत किए जाने वाले अपने दायित्वों का पालन नहीं किया।

इसके जवाब में ईरान ने भी मध्य पूर्व में स्थित अमेरिका के कई सैन्य ठिकानों पर बमबारी की। दोनों देशों के बीच लगातार हो रहे हमलों ने अंतरिम शांति समझौते को लगभग निष्प्रभावी बना दिया और दोनों पक्षों ने युद्धविराम की शर्तों का उल्लंघन किया।

इस बीच, एक अन्य मोर्चे पर ईरान समर्थित यमन के हूती विद्रोहियों और सऊदी अरब के बीच भी हमलों और जवाबी हमलों का सिलसिला जारी है। सऊदी अरब ने यमन में हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर मिसाइल हमले किए हैं।

सड़क दुर्घटना ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
बाबू पुत्र अर्जुनराम, मुकेश पुत्र मेहराराम, और हेमाराम पुत्र जीयाराम गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका अस्पताल में उपचार जारी है। हादसे की सूचना मिलते ही कानोड़ गांव सहित आसपास के क्षेत्रों के ग्रामीण बड़ी संख्या में जिला अस्पताल की मोर्चों पहुंच गए। पचपदरा थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने शवों का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

प्रदेश की सरकार हर मोर्चे पर बैकफुट पर है- सचिन पायलट

पायलट ने बाँसवाड़ा में दावा किया कि बड़ी संख्या में प्रधान, सरपंच व जिला प्रमुख कांग्रेस के बनेंगे

बाँसवाड़ा, 13 जुलाई। एआईसीसी महासचिव व प्रदेश के पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि प्रदेश की सरकार हर मोर्चे पर बैकफुट पर है। पंचायती राज और निकाय चुनाव नहीं कराना उसके डरे होने का सबसे बड़ा प्रमाण है। पायलट ने यह बात बाँसवाड़ा दौरे के दौरान सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में कही। पायलट ने कहा कि प्रदेश में वैचारिका एवं स्वास्थ्य, शिक्षा, इन्फ्रास्ट्रक्चर सब कुछ बिगड़ी हालात में है और प्रदेश की जनता ने सरकार रवानगी तय कर दी है।

एक सवाल के जवाब में पायलट ने केन्द्र और राज्य सरकार पर संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग का आरोप लगाया तथा कहा कि ईडी और चुनाव आयोग जैसी संस्थाएं भी वैमनस्य की भावना से कार्यवाही कर रही हैं।

पायलट ने अयोध्या में राम मंदिर में चंदा चोरी प्रकरण पर भी सवाल उठाये और कहा कि यही लोग कहते थे कि न खाऊंगा, न खाने दूंगा, लेकिन राम मंदिर में आये चंदे पर भी माल चंपत करके चंपत हो गये। पायलट ने कहा प्रदेश में कांग्रेस एकजुट है और पार्टी का एके-एक कार्यकर्ता मजबूती से आगामी दिनों में होने वाले पंचायती



कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव व पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट का कुशलगढ़ में कार्यकर्ताओं ने हल भेंट कर भव्य स्वागत किया।

राज व नगर निकाय चुनावों में शानदार जीत के लिये जुटा हुआ है। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में बड़ी मात्रा में प्रधान, सरपंच, जिला प्रमुख कांग्रेस के बनेंगे वाले हैं। बागड़ में बाप पार्टी पर अपनी प्रतिक्रिया में उन्होंने कहा कि हर एक

राजनैतिक दल का अपना एक नजरिया होता है और राजनैतिक पार्टियां अपने तौर तरीकों व विचारधारा से बनती, आगे बढ़ती और बिगड़ती रही हैं। इस दौरान बाँसवाड़ा विधायक व पाटी जिलाध्यक्ष अर्जुन सिंह नामनिया,

विधायक नानालाल निनामा, पूर्व सांसद रघुवीर मीणा, पूर्व उप जिला प्रमुख डॉ. विकास नामनिया, संगठन महासचिव मनीष पुन त्रिवेदी, अब्दुल गफ्फार, पूर्व सभापति राजेश टेनर, नवाब खां फौजदार, नगर कांग्रेस

■ **पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कुशलगढ़ में पूर्व प्रधान हलधिय खड़िया के श्रद्धांजलि समारोह में भी भाग लिया।**

अध्यक्ष धर्मेन्द्र तेली, अतीत गरासिया, पूर्व प्रधान सुनिता माल सहित अनेक नेता मौजूद रहे। इससे पूर्व सर्किट हाउस पहुंचने पर सैकड़ों की संख्या में उमड़े युवा कार्यकर्ताओं ने जोशीले नारे लगाते हुए सचिन पायलट का स्वागत किया। पायलट ने भी सभी कार्यकर्ताओं के सम्मान को स्वीकारा। देर रात तक सर्किट हाउस में मेला लगा रहा। इससे पूर्व, उन्होंने कुशलगढ़ में पूर्व प्रधान हरुतिंग खड़िया के श्रद्धांजलि समारोह में भाग लिया। कुशलगढ़ में भी पायलट की एक झलक पाने के लिये कार्यकर्ताओं में अपार उत्साह नजर आया। कार्यक्रम में पूर्व केबिनेट मंत्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीया, कांग्रेस जिलाध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री अर्जुन सिंह नामनिया, स्थानीय नेता हंसमुख सेठ आदि मौजूद थे।